छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 221 ■ अम्बिकापुर, गुरूवार 27 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

युवक का कमरे में मिला लहूलुहान शव, युवती भी अपना गला काटी

रक्षाबंधन पर घर जाने की बात को लेकर हुआ था विवाद, युवती का चल रहा उपचार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती ने भी अपना गला काट लिया, उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, दरिमा थाना क्षेत्र का मृतक मोहन पैकरा पिता परमानन्द पैकरा 25 वर्ष और सूरजपुर जिला के जयनगर थाना क्षेत्र की युवती महिमा सिदार एक दशक से साथ रह रहे थे। करीब दो माह से दोनों गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर में किराए के मकान में रह रहे थे। मोहन पैकरा मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन में युवती घर जाना चाहती थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच बुधवार की सुबह करीब 7 बजे विवाद हुआ। इसके बाद युवती शौचालय की ओर चली गई और युवक खुद का गला धारदार चीज से काट लिया, और लहूलुहान हाल में जमीन पर पड़ा था। युवती शौचालय से वापस आई तो प्रेमी को खून से लथपथ देखकर सहम गई, और शोर मचाया। इसके बाद युवती ने भी खौफनाक कदम उठाते हुए अपना गला काट लिया, जिसमें उसके गले के एक हिस्से में गहरा जख्म पहुंचा है, और सात टांके लगे हैं।

मकान मालिक का कहना है कि, जब वह वाशरूम से बाहर आया तो मोहन और महिमा में झगड़ा हो रहा था। इसे नजरअंदाज करके वह अपने घर के अंदर चले गया, और जिम जाने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की जोर से चिल्लाई, जब वह बाहर आया तो देखा खून से लथपथ मोहन पड़ा हुआ है। डॉयल 112 में कॉल करने के बाद वह अपने भाई के साथ गांधीनगर थाने में घटना की सूचना देने गया था। यहां से वापस आया तो लड़की भी अपने गला को काटने की कोशिश की थी, जिससे गहरा जख्म उभर आया था। डॉयल 112 की टीम उसे भी अस्पताल ले गई। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाने से पुलिस और एफएसएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों के स्वजन को घटना की जानकारी देने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल, पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि, युवक ने खुद अपना गला काटा या मामला कुछ और है।

जबरदस्ती नहीं की, सिर्फ पूछी थी

पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में महिमा सिदार ने बताया कि, मोहन पैकरा से वह पूछी रक्षाबंधन में घर चलोगे कि यहीं रहोगे? जबरदस्ती नहीं की, सिर्फ पूछी थी। इसी बात पर धीरे-धीरे विवाद होने लगा, उसके बाद वह वाशरूम चली गई थी। बाहर आकर देखी तो मोहन का गला कटा हुआ था। वह किसी को गला काटते नहीं देखी। दीवार पर खून के धब्बे लगे थे, और वो वहीं पड़ा था। मकान मालिक को चिल्लाकर वह इसकी जानकारी दी। इसके बाद वह अपना गला काट ली थी।

मोहन पैकरा और महिमा सिदार, साथ में करीब 10 साल से लिव-इन में रह रहे थे। सुभाषनगर में मंडल परिवार के यहां दो महीने पहले ही कमरा लिया था। बुधवार की सुबह लड़की ने रक्षाबंधन मनाने के लिए घर चलने कहा, तो लड़का जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर विवाद हुआ और लड़की वाशरूम चली गई, आई तो देखी मोहन अपना गला काट लिया है, इसे देखने के बाद लड़की ने भी अपना गला काट लिया। लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उसका इलाज चल रहा है और लड़के की मृत्यु हो चुकी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

दिलीप दुबे
थाना प्रभारी गांधीनगर

सामाजिक कार्यक्रम में गाली-गलौज करके गला दबाया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नगर निगम अंबिकापुर के सफाई विभाग में मैनेजर का काम करने वाले फरहान सिद्दीकी निवासी बसदेवापारा ने कोतवाली थाना में ईद के सामाजिक कार्यक्रम में मारपीट करने की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई है।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया है कि, 25 अगस्त को ईद त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा सामाजिक कार्यक्रम कलाकेन्द्र मैदान अंबिकापुर में रखा गया था। रात करीब 9.30 बजे वह भी कार्यक्रम में गया था। यहां पहले से मौजूद सद्दाम उर्फ ढिबरी निवासी मोमिनपुरा नूरानी मस्जिद के पास, उसे गाली देकर अपने पास बुलाया और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, और धक्का-मुक्की करके हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा और गला दबा दिया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।

छह साल के लिए भाजपा ने दुर्गाशंकर मिश्रा को पार्टी से किया निष्कासित

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी क्षेत्र के स्थानीय नेता और जिला संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके दुर्गाशंकर मिश्रा के खिलाफ बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई की है। भाजपा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय द्वारा निष्कासन का आदेश जारी किया गया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के बाद स्थानीय भाजपा संगठन में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दुर्गाशंकर मिश्रा क्षेत्र में पार्टी के सक्रिय नेताओं में शामिल रहे हैं और संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

ऐसे में उनके खिलाफ छह साल के निष्कासन की कार्रवाई को पार्टी स्तर पर कड़ा कदम माना जा रहा है। दुर्गाशंकर मिश्रा भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा विधायक रेणुका सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम कर रहे थे। रेणुका सिंह भाजपा की वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और पूर्व में केंद्र में राज्य मंत्री के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार में भी मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। ऐसे में उनके प्रतिनिधि के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है।

पार्टी गतिविधियों को प्रभावित करने का आरोप

प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर से जारी आदेश में दुर्गाशंकर मिश्रा पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने, संगठन की बैठकों और कार्यक्रमों को प्रभावित करने तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने जैसे आरोप लगाए गए हैं। संगठन के अनुसार इन शिकायतों और आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया। भाजपा संगठन ने साफ किया है कि पार्टी अनुशासन के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी के निर्णयों, बैठकों और कार्यक्रमों में अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। आरोपों के आधार पर संगठन ने दुर्गाशंकर मिश्रा को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया है।

बॉक्साइट खदान में 56 दिन से परिवहन बाधित करने वालों के विरूद्ध केस दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएमडीसी) की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदानों में एक मैनपाट के ग्राम बरीमा स्थित खदान में पिछले 56 दिनों से ग्रामीणों द्वारा परिवहन कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। खदान के अधिकारी इतने परेशान हो गए कि उन्हें आखिरकार पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी।

क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने थाना कमलेश्वरपुर में तत्संबंध में लिखित आवेदन देकर बताया है कि, कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2026 के तहत ग्राम बरीमा में स्थित बॉक्साइट खदान, रकबा 54.268 हेक्टेयर से वित्तीय वर्ष 2024-25 से पूर्व उत्पादित एवं खदान परिसर में भंडारित खनिज बॉक्साइट का नियमानुसार परिवहन कार्य कराया जा रहा है। शिकायत में बताया गया है कि 01.07.2026 के सुबह 08 बजे से 25.08.2026 के दिन 03 बजे तक ग्राम बरीमा निवासी कुंज बिहारी यादव एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा अवैध तरीके से शासकीय परिसर में खनिज बॉक्साइट के परिवहन कार्य व परिवहन मार्ग को रोक दिया गया है। आरोपी परिवहन मार्ग पर जमीन पर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और आने-जाने वाली वाहनों के चालकों को खदान में नहीं आने के लिए धमकाते हैं। पूर्व में भी कुंज बिहारी यादव एवं अन्य के द्वारा किए गए इस कृत्य के संबंध में प्रशासन को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया था। सीएमडीसी और ठेकेदार के प्रतिनिधियों द्वारा कई बार समझाइश दी गई कि, खनिज परिवहन कार्य को बाधित न किया जाए, बावजूद इनके द्वारा लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे खदान का पूरा अमला डरा हुआ है और खनिज बॉक्साइट का परिवहन कार्य बाधित होने से शासन के राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी कुंज बिहारी यादव व अन्य के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित सदर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है।

लीकेज ठीक करने बिना सुरक्षा के डैम में बुजुर्ग को उतारा, डूबने से मौत

जनाक्रोश को देखकर सिंचाई विभाग के अफसर भागे, अगले दिन निकाला गया शव

छ.ग.फ्रंटलाइन रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत नावाडीह में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संवेदनहीनता और लापरवाही से 55 वर्षीय बुजुर्ग राजकुमार मरावी की डूबने से मौत हो गई। राजकुमार डैम में जारी लीकेज को ठीक कराने के नाम पर इंजीनियर और चौकीदार ने बुजुर्ग को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के लगभग 20 फीट गहरे लबालब पानी से भरे तालाब में उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों के बढ़ते जनाक्रोश को देखकर सिंचाई विभाग के अफसर मौके से भाग निकले और थाने में जाकर छिप गए।

जानकारी के मुताबिक, पिछले एक महीने से त्रिकुंडा जलाशय से लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। इसे ठीक कराने के लिए सिंचाई विभाग के एसडीओ आशीष जगत, इंजीनियर निकेश पैकरा, स्थल सहायक अनिल कुमार गुप्ता, चौकीदार अहमद अली मौके पर पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद गांव के ही राजकुमार मरावी को बुलाया गया। बुजुर्ग के मना करने पर दोबारा ग्रामीण भेजकर उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया और बिना किसी सुरक्षा किट या लाइफ जैकेट के गहरे पानी में उतार दिया। लगभग आधे घंटे तक जब राजकुमार बाहर नहीं आया तो लकड़ी डालकर देखा गया। इसके बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए एक 15 साल के मासूम बच्चे के कमर में रस्सी बांधकर उसे गहरे पानी में उतार दिया। गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आया, वरना एक और बड़ा हादसा हो जाता। हादसा दोपहर लगभग 1 बजे हुआ, लेकिन किसी भी ग्रामीण या स्वजन को जानकारी देने की जगह चुपचाप भागकर थाने में छिपना जिम्मेदारों ने बेहतर समझा।

ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश-घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोपहर 3 बजे तक टीम को पत्थर और वॉटर आउटलेट होल के बीच फंसा शव दिख गया था। इसके बावजूद शाम 7 बजे तक तेज बहाव का हवाला देकर शव को नहीं निकाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि, टीम ने जनाक्रोश के डर से काम टाल दिया और रात हो जाने का बहाना बनाकर अगले दिन निकालने की बात कहते हुए लौट गई। जलाशय के पास शाम 7.30 बजे तक ग्रामीणों की भीड़ जमा रही और इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ था।

दोषियों पर अपराध दर्ज करने की मांग-ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के सभी दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। दूसरे दिन यानी बुधवार को शव निकाल कर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

5000 देने का लालच, फिर लौट के नहीं आए-मृतक राजकुमार मरावी की बहू देवंती मरावी का कहना हैं कि उनके ससुर दोपहर में खाना खा रहे थे, तभी एक लड़का बांध बनाने के लिए उन्हें बुलाने आया। ससुर ने जाने से मना कर दिया। सिंचाई विभाग के अफसर फिर से दूसरे लोगों को भेजे और कहा कि 500 रुपये देंगे। ससुर बोले कि उनका शरीर ठीक से नहीं चल रहा है, इतने में वो 1000 रुपये देंगे बोले, फिर बोले कि राजकुमार को उठाकर ले आओ उसको बांध बनाने के बदले 5000 रुपये देंगे। मेरे ससुर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैसे का लालच देकर जबरदस्ती ले गए। इसके बाद नहीं पता कि कैसे वे बांध में डूब गए।

प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए रायपुर, दुर्ग समेत 4 स्टेशनों पर लगेंगी प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीनें

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए 6 प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीनें लगाई जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों के इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक बोतलों को इन मशीनों में तुरंत क्रश किया जा सकेगा। इसके बाद क्रश की गई प्लास्टिक को रीसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर कुल 6 मशीनें लगाने की योजना है। इसका उद्देश्य स्टेशन परिसर में प्लास्टिक बोतलों को इधर-उधर फेंके जाने से रोकना और कचरे का व्यवस्थित तरीके से निपटारा करना है। यात्रियों को यह सुविधा जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। रायपुर के बाद इस सुविधा का विस्तार अन्य प्रमुख स्टेशनों तक किया जाएगा। अगले चरण में दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा-नेवरा और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशनों पर भी प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीनें लगाने की योजना है।

रेलवे के मुताबिक मशीनों से प्लास्टिक बोतलों का संग्रहण और क्रशिंग आसान होगा। इसके बाद प्लास्टिक को रीसाइकिल कर उपयोगी संसाधन में बदला जाएगा। इससे स्टेशन की सफाई बनाए रखने के साथ प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक बोतल और अन्य कचरा निर्धारित जगह पर ही डालें और उपलब्ध होने के बाद क्रशर मशीनों का इस्तेमाल करें। रेलवे का कहना है कि यह पहल स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को मजबूत करेगी।

सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 5 साल बाद रद्द की चार्जशीट

छ.ग.फ्रंटलाइन बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच तभी जारी रखी जा सकती है, जब सेवा नियमों में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान हो। बिना वैधानिक आधार के जांच जारी नहीं रखी जा सकती। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सेवानिवृत्त डिविजनल मैनेजर नंदकिशोर अग्रवाल की याचिका पर यह आदेश दिया।

मामला क्या था?-याचिकाकर्ता को 24 जुलाई 2019 को विभागीय आरोप-पत्र (चार्जशीट) जारी किया गया था। इसके 7 दिन बाद ही 31 जुलाई 2019 को वे सेवानिवृत्त हो गए। इसके बावजूद निगम ने उनके खिलाफ जांच जारी रखी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1984 में ऐसा कोई नियम नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद भी जांच जारी रखने की इजाजत देता हो। निगम ने अपने शपथपत्र में भी ऐसा कोई सक्षम प्रावधान नहीं दिखा पाया, सिर्फ कर्मचारी की परिभाषा का हवाला दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?-कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियोक्ता को विभागीय कार्यवाही शुरू या जारी रखने के लिए केवल प्रशासनिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसके लिए स्पष्ट वैधानिक आधार होना जरूरी है। सेवा विनियम में प्रावधान न होने से निगम के पास जांच जारी रखने की अधिकारिता ही नहीं थी।इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2019 की चार्जशीट को निरस्त कर याचिका स्वीकार कर ली।

मेन सब स्टेशन में केबल चोरी का असफल प्रयास

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर के मेन सब स्टेशन में मंगलवार की रात क्षेत्र में सक्रिय केबल कबाड़ चोरों ने केबल काट ले जाने का असफल प्रयास किया, हालांकि मौके पर उपस्थित कर्मचारियों की सजगता से चोर केबल नहीं ले जा पाए। बताया जा रहा है कि रीजनल स्टोर के पीछे एसईसीएल बिश्रामपुर का मेन सबस्टेशन है। यहां दर्जन भर से अधिक चोरों ने मध्यरात्रि में धावा बोल पहले पथराव किया। पथराव से सब स्टेशन में ड्यूटी कर रहे कर्मी सकते में आ गए और उन्होंने अपने बचाव में सब स्टेशन रुम में खुद को बंद कर सुरक्षा अमले को घटना की सूचना दी। ड्यूटी में उपस्थित इलेक्ट्रिशियन संजय सिंह एवं सब स्टेशन अटेंडेंट धर्मपाल द्वारा केबल चोरों द्वारा सब स्टेशन में अटैक की जानकारी देने पर बताया गया कि पेट्रोलिंग वाहन नहीं है।

इस दौरान चोरों ने केबल काट लिया और हो हल्ला और पकड़े जाने के भय से केबल ले जा नहीं सके हैं। बताया जा रहा है कि केबल काटने से सबस्टेशन का स्विच बंद हो गया है। बता दें कि बिड्डश्रामपुर क्षेत्र में केबल कबाड़ चोरों की सक्रियता बनी हुई है।

समय समय पर मौका देखकर बदमाश केबल और कबाड़ पार कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी पुलिसिया पूछताछ और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बचने चोरी मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराते हैं, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।

74.66 लाख की खाद की अफरा-तफरी पर प्रभारी प्रबंधक के खिलाफ जुर्म दर्ज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जयनगर में खाद के भंडारण और वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। समिति के गोदाम में उपलब्ध खाद और रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक के मिलान के दौरान कुल 6405 बोरी विभिन्न प्रकार की खाद कम पाई गई, जिसकी कुल कीमत 74 लाख 66 हजार 362 रुपए आंकी गई है। मामले में समिति के तत्कालीन प्रभारी समिति प्रबंधक सह खाद स्कंध प्रभारी श्यामलाल प्रजापति के विरुद्ध थाना जयनगर में धारा 316 (5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद सहकारिता विभाग से लेकर समिति स्तर तक हड़कंप की स्थिति है। जांच में एक ओर जहां डीएपी और यूरिया सहित विभिन्न खादों के स्टॉक में भारी कमी मिली, वहीं कुछ खाद का स्टॉक रिकॉर्ड की तुलना में अधिक भी पाया गया। जांच दल ने दस्तावेजों, पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक तथा मौके पर मौजूद खाद का भौतिक सत्यापन करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है। गौरतलब है कि 25 जुलाई 2026 को उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सूरजपुर द्वारा समिति जयनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान किसानों ने शिकायत किया कि उन्हें समिति से खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अगले ही दिन 26 जुलाई को खाद एवं बीज के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान समिति में भौतिक रूप से उपलब्ध खाद और पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक के बीच बड़ा अंतर सामने आया। जांच में 1349 बोरी डीएपी और 596 बोरी यूरिया कम मिली, जबकि 307 बोरी एसएसपी अधिक पाई गई। इसके बाद जांच दल ने 28 जुलाई को दोबारा भौतिक सत्यापन कराया। इस दौरान भी स्थिति में कोई खास

सुधार नहीं मिला। जांच में 1356 बोरी डीएपी, 502 बोरी यूरिया और 123 बोरी जिंक प्लस एसएसपी की कमी सामने आई, जबकि 429 बोरी एसएसपी पाउडर अधिक पाया गया। जांच प्रतिवेदन में समिति के खाद स्टॉक का पूरा गणित भी सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 को समिति में विभिन्न प्रकार की खाद का प्रारंभिक स्टॉक 1424 बोरी था। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से 30 जुलाई 2026 तक विपणन संघ से 16807 बोरी खाद समिति को प्राप्त हुई। इस तरह प्रारंभिक स्टॉक और प्राप्त खाद को मिलाकर समिति में 18231 बोरी खाद उपलब्ध होनी चाहिए थी। इनमें से किसानों को ऋण के रूप में 12677 बोरी खाद वितरित की गई। इस हिसाब से समिति के रिकॉर्ड के अनुसार 5554 बोरी खाद स्टॉक में शेष रहनी चाहिए थी। लेकिन जब जांच दल ने मौके पर भौतिक सत्यापन किया तो समिति के गोदाम में मात्र 362 बोरी विभिन्न प्रकार की खाद मिली। इस प्रकार रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच 5192 बोरी खाद की कमी पाई गई। जांच के अनुसार इस खाद की कीमत 7143975 रुपए है। मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि विपणन संघ द्वारा समिति को 1213 बोरी यूरिया अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई थी, जिसका भुगतान समिति द्वारा विपणन संघ को किया जाना अभी बाकी था। जांच के दौरान यह 1213 बोरी यूरिया भी समिति में उपलब्ध नहीं मिली।

इस खाद की कीमत करीब 3 लाख 32 हजार 264 रुपए 50 पैसे बताई गई है। इस तरह 5192 बोरी खाद की कमी और अतिरिक्त 1213 बोरी यूरिया को मिलाकर समिति में 6405 बोरी खाद का हिसाब नहीं मिला। जांच रिपोर्ट में इन 6405 बोरी खाद की कीमत 74 लाख 66 हजार 362 रुपए बताई गई है। सहकारिता विभाग की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन प्रभारी समिति प्रबंधक सह खाद स्कंध प्रभारी श्यामलाल प्रजापति द्वारा उक्त खाद स्टॉक का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के आधार पर समिति को 74.66 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचने की बात कही गई है।

विभागीय पत्र में इसे खाद की अफरातफरी कर गबन किए जाने का मामला बताया गया है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। प्रतिवेदन के आधार पर उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक द्वारा 14 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। विभागीय कार्रवाई के बाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा विश्रामपुर के शाखा प्रबंधक दिलीप दुबे द्वारा थाना जयनगर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन और जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 316 (5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। अब पुलिस द्वारा समिति के दस्तावेज, खाद वितरण रिकॉर्ड, पीओएस मशीन का डाटा, स्टॉक रजिस्टर, संबंधित कर्मचारियों के बयान तथा खाद की आपूर्ति और वितरण से जुड़े अन्य रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। जांच के दौरान यह भी सामने आने की संभावना है कि रिकॉर्ड में दर्ज खाद और वास्तविक वितरण के बीच अंतर किन परिस्थितियों में पैदा हुआ। फिलहाल 74.66 लाख रुपए की 6405 बोरी खाद के गायब होने का मामला जयनगर सहकारी समिति में खाद प्रबंधन और स्टॉक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों की शिकायत से शुरू हुई जांच अब पुलिस विवेचना तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में मामले में और तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

तीन सदस्यीय जांच दल ने तैयार की है रिपोर्ट

मामले की जांच के लिए उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सूरजपुर के आदेश 27 जुलाई को तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। इसमें जॉन केरकेट्टा अंकेक्षण अधिकारी प्रभारी, महेन्द्र राजवाड़े तथा नवीन कुमार सिंह, सहकारी निरीक्षक सहायक को शामिल किया गया था। जांच दल ने समिति के खाद भंडारण, वितरण, पीओएस रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का परीक्षण कर 11 अगस्त को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

दूध के दाम बढ़ाने पर पशुपालकों की बैठक में बनी सहमति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। क्षेत्र के पशुपालकों एवं दूध विक्रेताओं की बैठक बुधवार, 26 अगस्त को गौरीशंकर मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में पशुओं के चारे भूसा, दलिया, खल्ली-चुन्नी आदि के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए दूध के दाम बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 1 सितंबर से डेयरी में गाय का दूध 50 रुपये और भैंस का दूध 60 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। वहीं घर पहुंच सेवा में गाय का दूध 60 रुपये और भैंस का दूध 70 रुपये प्रति लीटर किए जाने पर सहमति बनी। पशुपालकों ने कहा कि निर्धारित तिथि से बढ़े हुए दाम लागू नहीं किए जाने की स्थिति में 2 सितंबर से दूध की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। बैठक में दूध विक्रेता संघ के बाबूलाल यादव, राजेश यादव, अमरेश प्रसाद, दीनानाथ यादव सहित आसपास के करीब दर्जनभर गांवों के दूध विक्रेता मौजूद रहे।

जेबीसीसीआई 12 में सिर्फ वेतन नहीं, मेडिकल से प्रमोशन तक फैसले की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोयला उद्योग में 12 वें वेतन समझौते जेबीसीसीआई 12 के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। वेतन समझौते की संभावित रूपरेखा के बीच भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने इस बार अपना एजेंडा और व्यापक कर दिया है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों के लिए केवल वेतन बढ़ोतरी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मेडिकल सुविधा, सिक लीव, अर्जित अवकाश, प्रमोशन, कैडर स्कीम और लंबे समय से लंबित मुद्दों पर भी एक साथ निर्णय होना चाहिए। संघ के महामंत्री सुजीत सिंह ने संगठन की आगामी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस बार प्रयास रहेगा कि जेबीसीसीआई 12 में ऐसे फैसले हों, जिनका लाभ कोयला कर्मचारियों को समझौते के बाद लंबे समय तक इंतजार किए बिना मिल सके। जेबीसीसीआई 12 के गठन की दिशा में अब 2 सितंबर को प्रस्तावित एपेक्स जेसीसी की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुजीत सिंह ने उम्मीद जताई कि बैठक में सकारात्मक पहल होगी और 12वें संयुक्त द्विपक्षीय समिति के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद जेबीसीसीआई 12 के गठन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उनका आरोप है कि इस मामले में कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया है। अब 2 सितंबर की बैठक में क्या रुख सामने आता है, इस पर कोयला कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों की नजर रहेगी।उन्होंने संकेत दिया कि वेतन विसंगतियों से जुड़े विषय को संगठन आगामी वेतन समझौते में मजबूती से उठाएगा, ताकि लंबे समय से कामगारों के बीच बनी असमानताओं और वेतन संबंधी सवालों का समाधान हो सके। वेतन के साथ मेडिकल, सिक लीव और ईएल पर भी फैसला संगठन का सबसे बड़ा जोर इस बार उन कर्मचारी सुविधाओं पर है, जिनके संबंध में अक्सर मुख्य वेतन समझौते के बाद भी निर्णय लंबित रह जाता है। समस्या यह है कि समिति की कई बैठकें होने के बावजूद कई मामलों में अंतिम निर्णय और आवश्यक ऑफिस ऑर्डर जारी होने में लंबा समय लग जाता है। इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ता है, जिन्हें सुविधा का लाभ मिलने के लिए लगातार इंतजार करना पड़ता है।संगठन अब चाहता है कि इन विषयों को केवल समितियों के भरोसे छोड़ने के बजाएं जेबीसीसीआई 12 के स्तर पर ही ठोस निर्णय की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। संघ ने साफ किया है कि इस मुद्दे को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने लेबर कोड को लेकर भी संगठन की आपत्तियां सामने रखीं। उन्होंने कहा कि लेबर कोड अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है और इसके कई प्रावधानों को लेकर बीएमएस का विरोध है। संगठन की ओर से इस संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्री को भी अवगत कराया गया है। बैठक में जेबीसीसीआई 12 के गठन को लेकर यदि सकारात्मक पहल होती है तो आगे वेतन समझौते की बातचीत का रास्ता साफ हो सकता है।

बिश्रामपुर स्टेशन पहुंच मार्ग बदहाल, 50 से अधिक गड्ढों में तब्दील हुई सड़क

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एनएच 43 से महज कुछ दूरी पर स्थित बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन का पहुंच मार्ग इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। सड़क पर जगह-जगह 50 से अधिक बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भरने से पैदल यात्रियों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।महत्वपूर्ण स्टेशन होने के बावजूद लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है। बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। वहीं क्षेत्र के इकलौते गुड्स शेड होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही भी इसी मार्ग से होती है। माल परिवहन और यात्री ट्रेनों से रेलवे को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने के बावजूद स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़क की हालत सुधारने की दिशा में ठोस पहल नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।

गिट्टी डालकर छोड़ दिया मार्ग

बताया जा रहा है कि करीब एक वर्ष पहले लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से

बिश्रामपुर गुड्स शेड में विभिन्न विकास कार्य कराए गए थे। इसके बावजूद गुड्स शेड से एनएच 43 तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। बारिश में कीचड़ से बचने के लिए सड़क पर क्रेशर की गिट्टी डालकर रोलर चला दिया गया था। इसका खामियाजा अब यात्रियों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सामान्य मौसम में जहां गिट्टी के कारण धूल के गुबार उड़ते हैं, वहीं बारिश में सड़क गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो जाती है।

25 लाख के प्रस्ताव पर भी नहीं बनी बात

स्टेशन पहुंच मार्ग के नवीनीकरण को लेकर ग्राम पंचायत कुंजनगर द्वारा एसईसीएल बिश्रामपुर प्रबंधन को सीएसआर मद से सड़क, नाली और स्टेशन चौक निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया गया था। तत्कालीन सरपंच के पत्र के बाद महाप्रबंधक ने सिविल विभाग को इस्टीमेट तैयार करने तथा जिला प्रशासन से एनओसी लेने के निर्देश दिए थे। करीब 25 लाख रुपये के कार्य का इस्टीमेट तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रस्ताव स्वीकृति के लिए एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर भेजा गया। लेकिन अलग-अलग कारणों से फाइल वापस किए जाने का सिलसिला चलता रहा। अंतत: सिविल विभाग ने आगे की कार्रवाई रोक दी।

रोजाना सैकड़ों लोग होते हैं परेशान

एनएच 43 के ठीक किनारे स्थित होने के कारण बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन का सरगुजा संभाग में खास महत्व है। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग प्रतिदिन ट्रेन पकड़ने यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा गुड्स शेड के कारण बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन भी इसी सड़क से गुजरते हैं।

भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क की स्थिति और खराब होती जा रही है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एसईसीएल का क्षेत्रीय मुख्यालय और बड़ी कोयला खदानें होने के बावजूद स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने कलेक्टर सूरजपुर से मामले में हस्तक्षेप कर रेलवे और एसईसीएल प्रबंधन से समन्वय स्थापित करते हुए सड़क का स्थायी निर्माण कराने की मांग की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा कर्मेश्वर का किया रुद्राभिषेक प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

★ ग्राम कर्रा में मंगल भवन निर्माण की घोषणा की ★ प्रदेश के शक्तिपीठों को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में जोड़ रही राज्य सरकार मुख्यमंत्री साय ★ अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बलरामपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को विकासखंड राजपुर अंतर्गत ग्राम कर्रा में आयोजित महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने प्राचीन बाबा कर्मेश्वर धाम में भगवान शिव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर ग्राम कर्रा में मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबा कर्मेश्वर की कृपा से यह क्षेत्र निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम कर्रा की पावन भूमि पर महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा का आयोजन होना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कथावाचक आचार्य दिव्यानंद जी महाराज को नमन करते हुए आयोजन समिति और समस्त श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर बनी रहे और प्रत्येक परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो।

छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने का हो रहा कार्य

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म, संस्कृति और आस्था की समृद्ध परंपराओं की भूमि है। यह माता कौशल्या की जन्मभूमि और प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेश के गांव-गांव में प्राचीन शिवालयों, देवी मंदिरों और लोक आस्था के केंद्रों की गौरवशाली परंपरा रही है। राज्य सरकार इस समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में जोड़ने की दिशा में कार्य

किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भगवान श्रीराम से गहरा और आत्मीय संबंध है। राज्य सरकार की रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन का अवसर मिल रहा है। अब तक लगभग 50 हजार श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था और तीर्थ दर्शन की अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए तीर्थ दर्शन योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत देशभर के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। अब तक लगभग 10 हजार श्रद्धालु इस योजना का लाभ लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कर चुके हैं।

शांति और विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा बस्तर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कर्मेश्वर के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दशकों तक हिंसा से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आज शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक परिवार तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्रा सहित बलरामपुर जिले में भी विकास कार्यों को निरंतर गति दी जाएगी। क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए यहां आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

सदियों पुरानी लोक आस्था का केंद्र है बाबा कर्मेश्वर धाम

ग्राम कर्रा स्थित बाबा कर्मेश्वर धाम क्षेत्र की लोक आस्था का प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां विराजमान शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। जनश्रुतियों के अनुसार लगभग नौवीं-दसवीं शताब्दी में साल के वृक्ष के खोल में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और तभी से यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में श्री कर्मेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है।

बाबा कर्मेश्वर से क्षेत्र की लोक मान्यताओं का भी गहरा संबंध है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार पुराने समय में जब क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी, तब ग्रामीण भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते थे। शिवलिंग पर गाय के गोबर का लेप लगाने की भी एक पारंपरिक मान्यता रही है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस अनुष्ठान के बाद क्षेत्र में वर्षा होती थी। पीढ़ियों से चली आ रही ऐसी लोक आस्थाओं ने बाबा कर्मेश्वर धाम को क्षेत्र की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है।

मां के नाम लगाया रुद्राक्ष का पौधा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाबा कर्मेश्वर धाम मंदिर परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम 3.0' अभियान के अंतर्गत अपनी माता श्रीमती जसमनी देवी साय के नाम पर रुद्राक्ष का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी मंदिर परिसर में बेल का पौधा लगाया। अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया।

इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, पत्थलगांव विधायक गोमती साय, आईजी दीपक झा, सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, सहित गणमान्य नागरिक और श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

बोनस गणना में अब 7 हजार से अधिक न्यूनतम मजदूरी भी बनेगी आधार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। देशभर के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बोनस से जुड़ी गणना में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पेमेंट ऑफ बोनस से संबंधित वेतन सीमा के प्रावधान को संशोधित किया है। इस बदलाव के बाद बोनस की गणना के लिए केवल 7 हजार प्रतिमाह की तय सीमा ही आधार नहीं रहेगी, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी यदि 7 हजार रुपए से अधिक है तो वही राशि बोनस गणना का आधार बनेगी। बताया जा रहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बोनस गणना से संबंधित प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार यदि बोनस के लिए पात्र कर्मचारी की मजदूरी 7 हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है, तो बोनस की गणना के लिए उसकी मजदूरी 7 हजार रुपए या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, दोनों में से जो अधिक हो, उसे माना जाएगा।इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी श्रेणी के कर्मचारी के लिए लागू केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी 7 हजार रुपए से अधिक निर्धारित होती है, तो बोनस की गणना में बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाया जा सकेगा। ज्ञात हो कि अब तक बोनस गणना में 7 हजार रुपए की सीमा को महत्वपूर्ण आधार माना जाता रहा है। नए प्रावधान में सरकार ने इस सीमा को न्यूनतम मजदूरी से जोड़ दिया है। ऐसे में भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी किए जाने पर उसका असर बोनस की गणना के आधार पर भी पड़ सकता है। कर्मचारियों के लिए यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि बोनस की गणना का आधार अब केवल एक स्थिर रकम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लागू न्यूनतम मजदूरी दर से भी जुड़ा रहेगा। इस संशोधन का वास्तविक लाभ उन पात्र कर्मचारियों को मिल सकता है, जिनके लिए लागू केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी 7 हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है। हालांकि किसी कर्मचारी को वास्तव में कितना बोनस मिलेगा, यह केवल इस संशोधन से तय नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी की बोनस पात्रता, वास्तविक मजदूरी, लागू न्यूनतम मजदूरी दर और पेमेंट ऑफ बोनस से जुड़े अन्य प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

अधिसूचना में 21 नवंबर 2025 से प्रभावी मानी जाने वाली अधिसूचना के संदर्भ में संशोधन का उल्लेख किया गया है। बोनस की गणना के आधार को न्यूनतम मजदूरी से जोड़ने के इस प्रावधान को श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वाड्रफनगर में ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी का खुलासा, 7 गिरफ्तार - 14 किलो चांदी और सोना बरामद

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलरामपुर-रामानुजगंज। वाड्रफनगर मार्केट स्थित अरविंद ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए 14.175 किलो चांदी और करीब 50 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं।मामला चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर का है। दुकान संचालक अरविंद सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 अगस्त की रात 9:15 बजे से 17 अगस्त सुबह 6:45 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरी की। चोर पायल, बिछिया, बच्चों के कड़े, अंगूठियां, सिक्के, चेन, मंगलसूत्र, सोने का कुंदा, नथ सहित बड़ी मात्रा में जेवरात ले गए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 133/2026 धारा 305, 331(4), 317(2), 5 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य से पकड़े गए आरोपी

एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। सुराग मिलने पर अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 7 आरोपियों को पकड़ा गया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम - सोनू कुमार, शंकर चौधरी, लीलू चौधरी, राजकुमार चौधरी, अंगद चौधरी, नरेन्द्र चौधरी और सुनील कुमार सोनी हैं।

पिकअप और बाइक से आए थे चोर

जांच में सामने आया कि आरोपी पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 26 जी 3631 और मोटरसाइकिल एमपी 15 केडी 7977 से वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस ने दोनों वाहन, मोबाइल फोन और नगदी भी जब्त की है।पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की चांदी को 60 हजार रुपए किलो के हिसाब से बेचने की योजना बताई है। पुलिस अब माल खरीदने-बेचने वाले अन्य लोगों और गिरोह के पुराने अपराधों की भी जांच कर रही है। इस पूरे खुलासे में थाना प्रभारी जितेन्द्र सोनी, निरीक्षक कुमार चंदन सिंह, साइबर सेल प्रभारी हिम्मत सिंह, उप निरीक्षक विमलेश सिंह सहित थाना और साइबर सेल टीम की अहम भूमिका रही। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

सावन के अंतिम मंगलवार पर सर्राफा संघ ने किया महामाया मंदिर में पूजन और विशाल भंडारा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के अंतिम मंगलवार को सराफा संघ अंबिकापुर द्वारा महामाया मंदिर प्रांगण में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम की शुरूआत पूजन-हवन और ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद सरस्वती कीर्तन मंडली, राजेंद्र साहू द्वारा भजन-कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।मंदिर के बाहर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रसाद वितरण के साथ-साथ बैठकर खाने की भी व्यवस्था की गई थी। इस भंडारे में हजारों की संख्या में मां के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह पूरा कार्यक्रम सराफा संघ के अध्यक्ष परशुराम सोनी के नेतृत्व में संपन्न हुआ।इस अवसर पर अरुण अग्रवाल, बजरंगी सोनी, वासुदेव सोनी, रविंद्र सोनी, राजेश सोनी, वीरेंद्र सोनी, पप्पू सोनी, किशोरी सोनी, कन्हैया सोनी, राजेंद्र सोनी, मुकेश सोनी, योगेश सोनी, आलोक सोनी, रमेश सोनी, पारस सोनी, चंद्रदीप सोनी, रामू सोनी, रघु सोनी, युगल किशोर सोनी, अजय सोनी, बलराम सोनी, रवि सोनी सहित युवा कार्यकताओं में शशि सोनी, ओम सोनी, अंशुल सोनी, रत्नेश सोनी, ऋषि सोनी, धर्मेंद्र सोनी, संतोष सोनी, संजय सोनी, गोपाल सोनी, मनी सोनी, चंदन सोनी, आनंद सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में सराफा संघ के सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महतारी वंदन योजना से दोगुनी हुई रक्षाबंधन की खुशियां, चंचल दास ने विष्णु भैया का जताया आभार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और त्योहारों की खुशियों का आधार बन गई है। ऐसी ही एक कहानी लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत उमरोली की चंचल दास की है। चंचल दास बताती हैं कि योजना शुरू होने से पहले वे पूरी तरह घरेलू महिला थीं और परिवार की आजीविका पति की कमाई पर निर्भर थी। महतारी वंदन योजना से हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की राशि ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।

रक्षाबंधन से पहले मिली 31वीं किस्त बनी सहारा

रक्षाबंधन 19 तारीख को है और उससे ठीक पहले महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त उनके खाते में आई। इससे उनके परिवार में त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गईं। चंचल दास ने बताया कि इस राशि से उन्होंने अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई और त्योहार की अन्य तैयारियां कीं।उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव

साय (विष्णु भैया) के लिए भी राखी भेजने की इच्छा जताई है, क्योंकि वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर कदम

चंचल दास कहती हैं, पहले छोटे-छोटे खर्चों के लिए भी सोचना पड़ता था। अब महतारी वंदन की राशि से मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेती हूं। त्योहारों पर परिवार के लिए कुछ ला पाती हूं तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने समय पर राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया।

सर्व समाज एकता मंच ने दिया शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शहर में सामाजिक सौहार्द, शांति और परस्पर सद्भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से ह्यसर्व समाज एकता मंच द्वारा एक भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों, धर्मों और समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

सद्भाव और स्वागत का माहौल

कार्यक्रम के दौरान सभी समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर आपसी भाईचारे और अमन-चैन की मिसाल पेश की। जुलूस और स्वागत स्थल पर उपस्थित सदस्यों ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया तथा पुष्प वर्षा कर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी आपसी एकता, शांति और विश्वास पर निर्भर करती है।

ह्यसर्व समाज एकता मंच का मुख्य उद्देश्य हर वर्ग के बीच परस्पर स्नेह और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि शहर में गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक समरसता सदैव अक्षुण्ण बनी रहे। समाज के सभी वर्गों ने एकजुट होकर शांति, सौहार्द और परस्पर सम्मान बनाए रखने का संकल्प लिया।

पुष्प वर्षा कर स्वागत

कार्यक्रम में शामिल अतिथियों और उपस्थित नागरिकों का फूलों की वर्षा व माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। शहरवासियों से किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और सद्भाव के साथ रहने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों एवं समाजसेवियों ने इस सफल आयोजन के लिए एक-दूसरे को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे सामाजिक एकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भिलाई चुनाव याचिका पर 31 अगस्त से हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) खारिज कर दी है। इसके बाद अब पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय द्वारा दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 31 अगस्त से नियमित सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भिलाई नगर सीट से देवेंद्र यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को हराया था। चुनाव

के बाद पांडेय ने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र यादव ने नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में आपराधिक मामलों, संपत्ति और अन्य जरूरी जानकारियों को पूरी तरह उजागर नहीं किया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे मतदाताओं के सामने उम्मीदवार की सही तस्वीर नहीं आ पाई। हालांकि इन आरोपों पर अभी कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी अर्जी

इससे पहले देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। 30 जून 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी मांग खारिज करते हुए कहा था कि मामले में उठे सवालों का फैसला केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं हो सकता, इसके लिए दोनों पक्षों के साक्ष्य, गवाहों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार

हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी एसएलपी खारिज कर दी। अब हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की नियमित सुनवाई चलेगी, जिसमें दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य और गवाह पेश करने होंगे। बताया जा रहा है कि इसी चुनाव विवाद से जुड़ी एक अन्य एसएलपी भी पहले सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है।

भाई का स्नेह, बहनों का अधिकार - बिहान से आत्मनिर्भर बनी निरा राजवाड़े, मछली पालन से बनेंगी लखपति दीदी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ह्यबिहान अहम भूमिका निभा रहा है। लखनपुर विकासखंड के ग्राम पुहपुटरा की निरा राजवाड़े इसकी मिसाल हैं। मुनिता स्व-सहायता समूह की सचिव निरा राजवाड़े ने बताया कि बिहान से जुड़ने के बाद समूह को 1 लाख 20 हजार रुपए का ऋण मिला। इस राशि से समूह की महिलाओं ने 10 वर्ष की लीज पर तालाब लेकर मछली पालन शुरू किया है।निरा बताती हैं कि पहले उनके पास कोई नियमित आजीविका का साधन नहीं था।

बिहान से जुड़ने के बाद समूह के माध्यम से सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिला। अब समूह की सभी महिलाएं मिलकर तालाब की देखरखाव, मछली पालन और बिक्री का काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।उन्होंने कहा कि मछली पालन से होने वाली आय से परिवार की जरूरतें पूरी होंगी और समूह की महिलाएं ह्यलखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस सहयोग के लिए निरा राजवाड़े ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (विष्णु भैया) का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहान योजना से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और परिवार में आर्थिक भूमिका मजबूत करने का मौका मिला है।

एक सप्ताह में अभियान चलाकर सड़कों के गड्ढे भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करें - जिलाधिकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में सड़क सुरक्षा यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के साथ ही बरसात के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने के लिए आदेशात्मक एवं विशेष अभियान चलाकर एक सप्ताह के अंदर सभी संबंधित विभाग कार्रवाई पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा आमजन की सुरक्षा से सीधे जुड़ा विषय है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, एनएचएआई/ टोल प्लाजा से संबंधित अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर गड्ढों को भरते हुए सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मार्गों पर अधिक गड्ढे हैं अथवा जहां दुर्घटना की संभावना अधिक है, उन्हें चिन्हित कर तत्काल मरम्मत कराई जाए।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक मार्ग की स्थिति, मरम्मत की प्रगति तथा लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़कों में गड्ढों के कारण यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारी/विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित एवं आवारा पशुओं को भी गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर ऐसे पशुओं को पकड़कर नियमानुसार गौशालाओं में संरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।

बिलासपुर हिरासत में मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की हत्या की एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। जनवरी 2024 में हुई हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त 2026 के आदेश के बाद सीबीआई ने सिविल लाइंस थाने में 30 जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 1036 को टेकओवर कर धारा 302 के तहत जांच शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि 13 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट पेश की जाए। फिलहाल सीबीआई की एफआईआर में आरोपी अज्ञात है।

क्या है पूरा मामला?

ग्राम मोहरा निवासी श्रवण सूर्यवंशी उर्फ सरवन तामरे (35) को पुलिस ने 17 जनवरी 2024 को पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि 18 जनवरी को उसके पास से 6 लीटर महुआ शराब बरामद हुई और आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर 19 जनवरी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।परिजनों के अनुसार 20 जनवरी को जब वे जेल में मिलने गए तो मिलने नहीं दिया गया। 21 जनवरी को जेल में तबीयत बिगड़ने पर पहले जेल अस्पताल और फिर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां 22 जनवरी को उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 36 घंटे तक पीटा गया।

न्यायिक जांच में क्या आया था?

22 जुलाई 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निकसन डेविड लकड़ा ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी। पोस्टमॉर्टम, हिस्टोपैथोलॉजी और एफआईआर रिपोर्ट में शरीर में कोई रासायनिक जहर नहीं मिला। मौत की वजह सिर में लगी चोट के कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताई गई। जांच में पत्नी लहराबाई सूर्यवंशी और पिता अमृतलाल ताम्र ने बयान दिया कि थाना सीपत पुलिस श्रवण को घर से ले गई थी और बाद में सिम्स में भर्ती होने की सूचना मिली।सुप्रीम कोर्ट का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई न सिर्फ

हिरासत में मौत की परिस्थितियों की जांच करेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन अधिकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं की, उनकी क्या भूमिका रही। कोर्ट ने राज्य सरकार को परिजनों को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अंतिम मुआवजा बाद में तय होगा।

सीबीआई की टीम ने शुरू की जांच

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 अगस्त को एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय सीबीआई टीम बिलासपुर पहुंची। टीम ने सिविल लाइन थाने से केस डायरी जब्त की और सेंट्रल जेल जाकर जेल अधीक्षक व स्टाफ से पूछताछ की।

सम्पादकीय

युद्ध भले ही बंद हो, लेकिन होर्मुज में बना रहेगा संकट

खाड़ी क्षेत्र में भले ही युद्धविराम हो गया हो, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट खत्म होने के बजाय नए रूप में सामने आता दिखाई दे रहा है। यहां अब सीधा सैन्य टकराव ही सबसे बड़ी चिंता नहीं है, बल्कि समुद्री मार्ग पर नियंत्रण, आर्थिक दबाव और रणनीतिक प्रभुत्व की होड़ अधिक गंभीर होती जा रही है। ईरान की संसद द्वारा होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देना इसी बदलते समीकरण का संकेत है। ईरान का तर्क है कि जहाजों से लिए जाने वाले शुल्क के बदले उन्हें समुद्री सेवाएं, सुरक्षा, इंश्योरेंस, पर्यावरण संबंधी सुविधाएं और विशेष परिस्थितियों में ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की दूसरी मुद्रा में किया जा सकेगा। देखने में यह व्यवस्था एक सामान्य सेवा शुल्क जैसी लग सकती है, लेकिन होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग के संदर्भ में इसका महत्व कहीं अधिक है। सवाल केवल टोल वसूली का नहीं, बल्कि यह है कि इस जलडमरूमध्य में अंतिम नियंत्रण किसका होगा। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। इसलिए यहां आवाजाही पर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ सकती है और उसका प्रभाव महंगाई के रूप में दुनिया के अनेक देशों में दिखाई दे सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और तेज करने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का यह कहना कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग के आखिरी दौर में पहुंच गया है, यह बताता है कि वाशिंगटन का लक्ष्य केवल सैन्य दबाव तक सीमित नहीं है। ईरान की आय के बड़े स्रोतों को रोकने की कोशिश उसके आर्थिक ढांचे पर दबाव बढ़ा सकती है। ऐसे में ईरान का होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने का फैसला आर्थिक दबाव का जवाब भी माना जा सकता है। स्थिति को और संवेदनशील ईरान की खाड़ी देशों को दी गई चेतावनी बनाती है। अमेरिका के आर्थिक अभियान में सहयोग करने वाले देशों को दुश्मन मानने की बात क्षेत्रीय देशों के लिए सीधा संदेश है। खाड़ी देशों के सामने अब सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। यदि यह तनाव बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद राजनीतिक विभाजन और गहरे हो सकते हैं। सबसे चिंताजनक पहलू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होर्मुज को 'न्यू यूएस टेरिटरी' बताना है। यदि दुनिया के एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग को लेकर अमेरिका और ईरान जैसी शक्तियां अपने-अपने नियंत्रण का दावा करने लगती हैं, तो इससे टकराव की आशंका बढ़ेगी। युद्धविराम निश्चित रूप से राहत देता है, लेकिन वास्तविक शांति तभी मानी जाएगी जब होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर भरोसा कायम हो। यदि युद्ध की जगह आर्थिक प्रतिबंध, टोल, समुद्री नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शन ले लेते हैं, तो संकट का स्वरूप भले बदल जाए, खतरा बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका, ईरान और खाड़ी देश टकराव बढ़ाने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं। होर्मुज में शांति केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी अनिवार्य है।

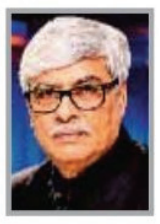

मुद्दा
ओमकार चौधरी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिलीगुड़ी दौरा पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर केंद्र की नई रणनीति का संकेत देता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा को जोड़कर त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार करने की योजना सामने आई है। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा, सैन्य तैयारियों, खुफिया तंत्र, केंद्रीय बलों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। चीन और बांग्लादेश की बढ़ती रणनीतिक निकटता, नेपाल-भूटान से जुड़ा संवेदनशील भूगोल और संभावित गैर-पारंपरिक खतरों के बीच यह पहल महत्वपूर्ण है। इसे युद्ध की आशंका नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा गहराई बढ़ाने की तैयारी के रूप में देखा जाना चाहिए।

सिलीगुड़ी में त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का सिलीगुड़ी दौरा केवल सीमा सुरक्षा की सामान्य समीक्षा भर नहीं माना जाना चाहिए। 21–22 अगस्त 2026 को सिलीगुड़ी में हुई गतिविधियों और उच्चस्तरीय बैठक से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार भारत के अत्यंत संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर या 'चिकन नेक' की सुरक्षा को अब अधिक समन्वित और बहुस्तरीय ढांचे में देख रही है। अमित शाह ने स्वयं तीन रणनीतिक स्थानों असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा को जोड़कर एक 'त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड' तैयार किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने इसे तीन नए सैन्य ठिकानों वाला सुरक्षा ढांचा बताया। इसके साथ सीमा निगरानी, बाड़बंदी, केंद्रीय बलों, खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। इस तैयारी को समझने के लिए सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भूगोल समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में स्थित यह संकरा भूभाग मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला प्रमुख स्थलीय संपर्क है। इसके आसपास नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, जबकि उत्तर में सिक्किम और उसके आगे चीन का तिब्बत क्षेत्र है। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की सड़क और रेल संपर्क व्यवस्था में इस क्षेत्र का असाधारण महत्व है। इसीलिए अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा क्षेत्र बताया है। यहां किसी गंभीर सैन्य संकट, बड़े आतंकवादी हमले, तोड़फोड़ अथवा आपूर्ति मार्ग बाधित होने की स्थिति का प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा; उसका असर पूरे पूर्वोत्तर से भारत के संपर्क पर पड़ सकता है।

नई व्यवस्था की विशेषता यह है कि सरकार सुरक्षा को केवल कॉरिडोर की सबसे संकरी पट्टी पर केंद्रित नहीं रखना चाहती। धुबरी, किशनगंज और चोपड़ा को देखें तो एक व्यापक त्रिकोण दिखाई देता है। असम का धुबरी बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में है। किशनगंज बिहार का वह जिला है जो उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले भूगोल से जुड़ता है, जबकि चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में सिलीगुड़ी की दक्षिणी दिशा में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। लेकिन सवाल है कि इसी समय इतनी गंभीर तैयारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर भारत के पूर्वी पड़ोस में तेजी से बदल रहे सामरिक वातावरण में है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पिछले दो वर्षों में उस सहजता में नहीं रहे जो शेख हसीना के शासनकाल में लंबे समय तक दिखाई देती थी। अगस्त 2024 में हसीना के सत्ता से हटने और भारत आने के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर अविश्वास बढ़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत और बांग्लादेश किसी सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी धारणा के लिए वर्तमान में कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की योजना केवल वर्तमान राजनीतिक इरादों के आधार पर नहीं बनाई जाती; उसमें संभावित परिस्थितियों और क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा, पूर्वोत्तर का भूगोल, अवैध आवाजाही, तस्करी और सीमापार अपराध जैसी समस्याएं पहले से मौजूद हैं। यदि राजनीतिक संबंधों में अविश्वास जुड़ता है तो सीमा प्रबंधन का महत्व स्वतः बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में

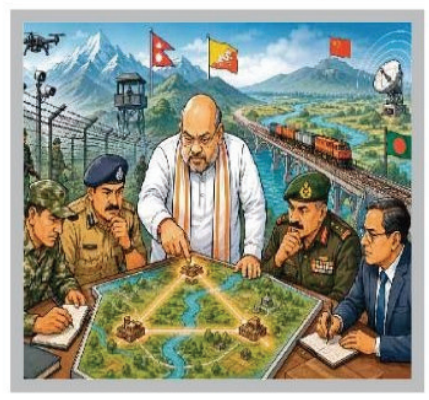

अमित शाह द्वारा बाड़बंदी पर दिया गया जोर महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा परिवर्तन चीन और बांग्लादेश की बढ़ती निकटता है। चीन लंबे समय से बांग्लादेश का प्रमुख आर्थिक और रक्षा साझेदार है। बांग्लादेश चीनी हथियारों का बड़ा ग्राहक रहा है और चीन वहां बुनियादी ढांचा तथा रक्षा-संबंधी परियोजनाओं में सक्रिय है। भारत के लिए समस्या भूगोल से और गंभीर हो जाती है। चीन पहले से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत का प्रमुख सैन्य प्रतिद्वंद्वी है। सिक्किम के उत्तर और पूर्व में चीनी सैन्य ढांचा मौजूद है और 2017 का डोकलाम संकट दिखा चुका है कि भूटान–सिक्किम–तिब्बत क्षेत्र की सामरिक स्थिति सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भारतीय चिंताओं से जुड़ सकती है। यदि इसी समय बांग्लादेश में चीन का रक्षा और रणनीतिक प्रभाव बढ़ता है, तो भारतीय योजना निर्माताओं को उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं को ध्यान में रखकर आपातकालीन योजना तैयार करनी होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि चीन और बांग्लादेश भारत पर संयुक्त हमले की तैयारी कर रहे हैं; इसका अर्थ यह है कि भारत अपने सबसे संवेदनशील संपर्क क्षेत्र की सुरक्षा को किसी एक दिशा से आने वाले खतरे तक सीमित नहीं रख सकता। यहीं धुबरी–किशनगंज–चोपड़ा त्रिकोण की रणनीतिक उपयोगिता दिखाई देती है। किसी संकट में सुरक्षा केवल सीमा पर सैनिक खड़े करने का प्रश्न नहीं होती। सैन्य बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तेजी से स्थानांतरित करना, गोला-बारूद और रसद पहुंचाना, सड़क तथा रेलवे संपर्क सुरक्षित रखना, महत्वपूर्ण पुलों और संचार केंद्रों की रक्षा करना तथा किसी तोड़-फोड़ के बाद वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक होता है। सुरक्षा ग्रिड का उद्देश्य यदि इसी प्रकार की अतिरेकता पैदा करना है तो यह 'चिकन नेक' की पुरानी कमजोरी को केवल अग्रिम रक्षा के बजाय गहराई में फैली सुरक्षा संरचना से संबोधित करने का प्रयास है। तीसरा तत्व पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की भारत-विरोधी बयानबाजी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां स्वाभाविक रूप से नोट करती हैं। लेकिन 'इस बार पूर्वी दिशा से हमला होगा' जैसे किसी विशिष्ट कथित बयान को आधिकारिक सैन्य तथ्य मानने से पहले उसके मूल संदर्भ और शब्दशः प्रमाण की पुष्टि आवश्यक है। इसीलिए सिलीगुड़ी में 22 अगस्त की बैठक में केवल सैन्य उपस्थिति नहीं, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। यही आधुनिक 'ग्रिड सुरक्षा' का महत्वपूर्ण तत्व है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की एक और विशेषता है कि इसके आसपास भारत की अलग-अलग प्रकार की सीमाएं हैं। नेपाल और भूटान के साथ भारतीय संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और वहां सीमा प्रबंधन की प्रकृति बांग्लादेश या चीन सीमा से अलग है। लेकिन खुली या अपेक्षाकृत सुगम आवाजाही वाली सीमाओं का दुरुपयोग आपराधिक या शत्रुतापूर्ण नेटवर्क कर सकते हैं। इसीलिए सशस्त्र सीमा बल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यही धुबरी, किशनगंज और चोपड़ा के त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड का व्यापक सामरिक अर्थ है। भारत अपनी सबसे चर्चित भौगोलिक कमजोरी को केवल बचाने की नहीं, बल्कि उसके चारों ओर ऐसी सुरक्षा गहराई तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसमें सीमा सुरक्षा, सैन्य तत्परता, खुफिया जानकारी, पुलिस व्यवस्था और आधारभूत ढांचे की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हों। सेंट मार्टिन और बंगाल की खाड़ी में बदलती भू-राजनीति से लेकर बांग्लादेश–चीन निकटता और हिमालयी सीमाओं तक यदि पूरे पूर्वी क्षेत्र को एक ही सामरिक मानचित्र पर रखा जाए, तो अमित शाह की सिलीगुड़ी बैठक का महत्व कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जल प्रदूषण

ज्ञानेन्द्र रावत

आखिर कौन बनेगा यमुना का भगीरथ

देश में पुण्य दायिनी नदी गंगा के बाद दूसरी प्रमुख नदी यमुना का प्रदूषण चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण उसका प्रदूषण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कारण उसका 85 फीसदी से ज्यादा प्रदूषण बिना ट्रीट किए घरेलू कचरे और औद्योगिक रसायन युक्त अपशिष्ट से है। इस बारे में दिल्ली सरकार बरसों से दावे-दर-दावे करती रही है। बीता इतिहास इसका जीता-जागता सबूत है। केजरीवाल ने भी यमुना के शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया था। उनके भी कार्यकाल ने यमुना की सफाई की दिशा में दावों और घोषणाओं के मामले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और आलोचनाएं भी झेली थीं। अब यदि दिल्ली के जल संसाधन मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की मानें तो अब यमुना की सफाई अलग-अलग परियोजना के माध्यम से नहीं, वरन दिल्ली की पूरी सीवर अवसंरचना में व्यापक बदलाव के जरिये की जा रही है। उनका मानना है कि यमुना तब साफ होगी जबकि हर घर सीवर नेटवर्क से जुड़ा होगा। हर बूंद सीवेज का उपचार होगा। इसी बदलाव की शुरुआत हमने की है। ये रहा उनका दावा। अब जरा हालात का भी जायजा लें। सबसे पहले देश की पतितपावनी और मुक्तिदायिनी नदी गंगा को लें जिसका जल पुण्य का सबब माना जाता है। वही मोक्षदयिनी नदी गंगा अपने मायके उत्तराखंड में ही मैली है। इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट कर ही चुकी है। आज तक 1985 से लेकर गंगा प्रदूषण मुक्ति हेतु 42,000 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। गंगा एक्शन प्लान पर शुरुआत में ही 1200 करोड़ की राशि खर्च की गई। लेकिन हालात गवाह हैं कि आज उसका जल पुण्य का नहीं, मौत का सबब बन गया है। यमुना आज तमिलनाडु की कूवन नदी सहित देश की सबसे प्रदूषित नदी है। उसकी सफाई पर अब तक हुए खर्च की बात करें तो संसद में दिए आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 5,536 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। जबकि यमुना संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर पहले ही लगभग 1,951 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट के तहत दिल्ली जल बोर्ड को 6485 करोड़ रुपये की राशि दी गई और अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 4500 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। यही नहीं यमुना के जल को साफ करने के साथ साथ नजफगढ ड्रेन की सफाई के लिए 1000 करोड़ की परियोजनाओं को दिल्ली सरकार ने और मंजूरी दी है। मछलियों में मिले माइक्रो प्लास्टिक में 77.8 फीसदी हिस्सा कपड़ों और धागे के सूक्ष्म रेशों का था। इसका मुख्य कारण सिंथेटिक कपड़े, घरेलू धुलाई, टैक्सटाइल उद्योग और रसायन युक्त अपशिष्ट जल का बहाव है। अब जरा यमुना के पानी में जहरीले रसायनों की बात करें तो पाते हैं कि हकीकत में यमुना के पानी में अमोनिया की सीमा अधिकांश एसटीपी को भी बाधित करती है। बी ओ डी का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है और घुलित आक्सीजन का स्तर अक्सर 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम होने से जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। मानव और पशु मल-मूत्र से आने वाले वैक्टीरिया का स्तर सीमा से 32,000 गुणा से भी ज्यादा है। यह खतरे का संकेत है। वैसे तो यमुना की दशा पूरे प्रवाह क्षेत्र में शोचनीय है, लेकिन यदि देश की राजधानी दिल्ली के 22 किलोमीटर इलाके की ही बात करें तो यमुना अपनी बदहाली की कहानी खुदबखुद बयां करती है। यहां का जल फीकल कोलिफार्म, लैड जैसी भारी धातुओं और डिटर्जेंट से इतना प्रदूषित है कि इसके संपर्क में आने से लोग कैंसर, गंभीर त्वचा रोग, सांस, पेट के संक्रमण, लिवर, तंत्रिका तंत्र आदि जानलेवा रोगों का शिकार हो रहे हैं। हकीकत यह है कि देश में यमुना ही नहीं गंगा, वरुणा, रोहिणी, पांडु, ईशन, सई, घाघरा, काली, गोमती, रामगंगा, कोसी, राप्ती, तमसा, सरयू, नीमा, बीटा, सेंगर, अरिंद, सरायन, करवन, काक, उल्ल जैसी देश की तकरीब चार सौ से अधिक नदियों में सीवेज का गंदा पानी 1385 से भी ज्यादा गंदे नालों के जरिए बहाये जाने के मामलों में बीते बरसों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गयी है। फिर भी देश के भाग्य विधाता मौन हैं। अब सवाल यह है कि यमुना बरसों से निर्देशों, दावों के जाल में उलझी है। पिछले मुख्यमंत्री तो यमुना साफ होगी और वे उसमें नहाने के दावे करते-करते पद से ही मुक्त हो गये, कोई यमुना को टेम्स बनाने का दावा करते-करते दुनिया से ही विदा हो गया, लेकिन यमुना अपनी बदहाली पर दशकों से रो रही है। सरकारें तो सरकारें लगता है, दिल्ली की जनता की आत्मा मर गयी है। उसको अपनी जीवन की रेखा कही जाने वाली यमुना की बदहाली की कोई चिंता ही नहीं है। यमुना फिर भी मैली की मैली ही रहती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शक्ति, मुक्ति और विजय की यात्रा है ज्ञान

ज्ञान शक्ति है, ज्ञान ही मुक्ति भी और ज्ञान ही विजय की यात्रा है। जिसे हम जान लेते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं और जिसे हम जान लेते हैं, उसे हम जीत भी लेते हैं। हमारी हार और पराजय हमारे अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंधकार है, इसीलिए पराजय है। प्रकाश हो तो पराजय असंभव है। प्रकाश विजय

सद्गुरु निर्गुण निराकार का साकार स्वरूप

सौ चांद एवं हजार सूर्य भी उदय होकर संसार को प्रकाशित कर रहे हों परंतु सद्गुरु नहीं है तो घोर अंधकार ही है। सद्गुरु सूर्य की भांति होते हैं। सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए किसी मशाल या किसी दीये की आवश्यकता नहीं होती। सूर्योदय होते ही स्वतः प्रकृति में सूर्य की उपस्थिति का आभास हो जाता है।

संकलित
दर्शन

बन जाता है। मृत्यु के संबंध में पहली बात आपसे यह कहना चाहूंगा कि मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है लेकिन मृत्यु ही सत्य मालूम होती है। न केवल सत्य मालूम होती है, बल्कि जीवन का केंद्रीय सत्य भी वही मालूम होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है और चाहे हम भूल जाते हों, भुला देते हों, लेकिन फिर भी मृत्यु चारों तरफ निकट ही खड़ी रहती है। अपनी छाया से भी ज्यादा अपने पास मृत्यु है। जीवन का जो रूप हमने दिया है, वह भी मृत्यु के भय के कारण ही दिया है। मृत्यु के भय ने समाज बनाया है, राष्ट्र बनाए हैं, परिवार बनाए हैं, मित्र एकत्रित किए हैं। मृत्यु के भय ने धन एकत्रित करने की दौड़ दी है, मृत्यु के भय ने पदों की आकांक्षा दी है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु के भय ने ही हमारे भगवान और हमारे मंदिर भी खड़े कर दिए हैं। मृत्यु से भयभीत घुटने टेककर प्रार्थना करते हुए लोग हैं। मृत्यु से भयभीत आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ हाथ जोड़े हुए लोग हैं।

संकलित
प्रेरणा

पेड़-पौधे, फूल-कलियां, पशु-पक्षी, जड़-चेतन में स्फुरण हो जाता है अर्थात प्राणों का संचार हो जाता है। इसी प्रकार प्रबल उत्कंठा रखने वाले जिज्ञासु के जीवन में जब सद्गुरु रूपी सूर्य का उदय होता है, तो जन्मों का अज्ञान तिमिर समाप्त होकर ज्ञान उजाला हो जाता है। निर्गुण निराकार का साकार स्वरूप सद्गुरु होता है, जिस प्रकार सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं परंतु उसी के प्रकाश से जब चंद्रमा उदय होता है तो हम सभी उसको निहारते हैं, शीतलता का आनंद प्राप्त करते हैं, प्रेमीजन एक भिन्न प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं इसी प्रकार भक्तजन ईश्वर के निराकार रूप में वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाते जो कि परब्रह्म के साक्षात स्वरूप सद्गुरु के दिव्य दर्शन करके प्राप्त करते हैं। गोपियां सद्गुरु श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए थकतीं नहीं थीं एवं प्रेम में उनकी सुध-बुध सब विस्मृत हो जाती थी। एक क्षण के लिए विलग नहीं हो पाती थीं इसी प्रकार भक्तजन सद्गुरु से कतई विलग नहीं हो पाते, क्योंकि भक्तजनों के लिए सद्गुरु पिंड प्राण होते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

विज्ञान की भी अपनी सीमाएं

वैसे तो विज्ञान ने हर असंभव को संभव बनाने के लिए बहुत काम किया है और काफी हद तक सफल भी हुआ है। मानव को आज हर सुविधा और आराम उपलब्ध है, परंतु न तो कैंसर जैसे असाध्य रोग की अचूक औषधि खोज पाया और न ही ऐसी दवाई ही खोजी जो मनुष्य को सदैव स्वस्थ और बुढ़ापे के लक्षणों से सदा के लिए निजात दिला सके। यह बात लगेगी सभी को बेतुकी और प्रलाप मात्र, पर यह यक्ष प्रश्न है, जिसके समक्ष आकाश की खोज खबर लेने वाला मानव असहाय दिखता है। यह वैज्ञानिकों को एक खुली चुनौती है। भले ही हरिद्वार के इम्युनोट के वैज्ञानिकों ने प्राचीन भारतीय आयुर्वेद को इस कार्य करने में सक्षम कहा है। लेकिन संसार को कब यह दवाई उपलब्ध होगी, इसका इंतजार है।

–अंकित धनखड़, रोहतक

ट्रेंड

तीन भगोड़े पकड़े

मलेशिया में बंधीहा गिरोह के तीन भगोड़े अपराधियों को पकड़कर भारत लाया गया है और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भगोड़े अपराधियों में जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह शामिल हैं।

-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

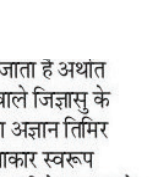

अथर्ववेद पढ़ें राहुल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। वे अर्बन नक्सलियों के हाथों देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर वे मनुस्मृति को समझना चाहते हैं तो अथर्ववेद पढ़ें।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उत्तर प्रदेश

तेलंगाना का विकास रोक रहे

केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल संसद में यह मुद्दा उठाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका यात्रा की अनुमति दे दी, लेकिन मुझे नहीं दी। मुझे अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं देना तेलंगाना के विकास को रोकना है। -रेवंत रेड्डी, सीएम, तेलंगाना

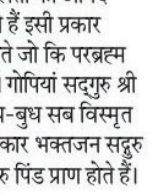

मतदाताओं के नाम हटाए

लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए हैं; अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जनगणना की कवायद एनआरसी लागू करने की चोर-दरवाजे से की गई एक और कोशिश है।

-ममता बनर्जी, पूर्व सीएम, प. बंगाल

करंट अफेयर

मक्का एग्रीमेंट की खटास मिटाने ईरान जाएंगे मुनीर!

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान का दौरा करेंगे। तेहरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि यह दौरा इलाके में शांति और सुरक्षा लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए है। हालांकि, मुनीर का दौरा ऐसे वक्त हो रहा, जब मक्का एग्रीमेंट में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने साइन किए हैं। वहीं, होर्मुज को लेकर अमेरिका से ईरान का विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इसका मकसद उस युद्ध को खत्म करना है, जो फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद शुरू हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से मुनीर के दौरे की पुष्टि की है। पहले सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा है कि ईरान और पाकिस्तान सीधे संपर्क में हैं। दूसरे सूत्र ने कहा है कि बातचीत में संघर्ष से जुड़ी हालिया घटनाओं पर भी चर्चा होगी। इसमें ईरान पर और कड़े बैन लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी शामिल है। असल में मुनीर का दौरा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच हो रहा है। ईरान ने बैन की अमेरिकी पॉलिसी के जवाब में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है।

ऑफ बीट

मनोकामनाएं पूरी करते हैं प्रयागराज के ताले वाले महादेव

प्रयागराज में भगवान शिव का एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां भक्त अपनी मनोकामना को ताले में बांधकर भोलेनाथ के चरणों में छोड़ देते हैं। नाथेश्वरनाथ महादेव मंदिर को लोग प्यार से 'ताले वाले महादेव मंदिर' के नाम से भी जानते हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करते हुए मंदिर परिसर में एक ताला लगाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर की परंपरा बाकी शिवालयों से इसे अलग बनाती है। श्रद्धालु ताले पर अपना नाम, पता या पहचान लिखकर उसे मंदिर की जाली, दीवार या परिसर में किसी निर्धारित जगह पर लगा देते हैं। इसके बाद वे अपनी इच्छा पूरी होने का इंतजार करते हैं। जब मनोकामना पूरी होने का विश्वास होता है, तो भक्त दोबारा मंदिर पहुंचकर उसी ताले को खोलते हैं और भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर में लगे अनगिनत ताले यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और उम्मीद की झलक दिखाते हैं। हर ताला किसी व्यक्ति की अपनी प्रार्थना और विश्वास की कहानी कहता है। समय के साथ जब तालों की संख्या बढ़ जाती है, तो पुराने तालों को हटाकर सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। इसके लिए मंदिर परिसर में एक कमरा भी बनाया गया है, जहां पुराने ताले रखे जाते हैं।

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर डोंगरी चिल्ड्रन होम में लंगर-ए-रसूल की तकसीम

मुंबईः जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर रजा एकेडमी की जानिब से डोंगरी स्थित चिल्ड्रन होम में बच्चों के बीच लंगर-ए-रसूल तकसीम किया गया।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साहिल अग्रवाल(SAHIL AGRAWAL), पिता कैलाश चंद अग्रवाल(KAILASH CHAND AGRAWAL), निवासी मकान नं. 96, नवापारा एसबीआई कॉलोनी, वार्ड नं. 9, अंबिकापुर, पोस्ट ऑफिसः अम्बिकापुर, जिलाः सरगुजा, छत्तीसगढ़ - 497001 हूँ। मैंने अपना पुराना नाम साहिल अगरवाल(Sahil Agarwal, पिता कैलाश चंद अगरवाल(KAILASH CHAND AGARWAL), बदलकर अपना नया नाम साहिल अग्रवाल, पिता कैलाश चंद अग्रवाल कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम साहिल अग्रवाल, पिता कैलाश चंद अग्रवाल, के नाम से सभी शासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में जाना एवं पहचाना जाए।

शपथकर्ता

साहिल अग्रवाल

मकान नं. 96, नवापारा एसबीआई कॉलोनी, वार्ड नं. 9

अम्बिकापुर, पोस्ट ऑफिसः अंबिकापुर

जिलाः सरगुजा (छ.ग.) - 497001

राहुल और खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जताई आपत्ति

जनगणना का मौजूदा स्वरूप हमें अस्वीकार इस प्रश्नावली को रद्द करके नई बनाई जाए

▶▶ नई दिल्ली

राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक चर्चा के बाद नई प्रश्नावली तैयार करें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना की प्रश्नावली पर आपत्ति जताई है और आग्रह किया कि इस प्रश्नावली को रद्द कर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक चर्चा के बाद नई प्रश्नावली तैयार की जाए।

कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं का कहना है कि जनगणना का वर्तमान स्वरूप स्वीकार नहीं है तथा जातियों और समुदायों की सही संख्या तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन तभी संभव है, जब जाति की पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे और राहुल गांधी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि भारत में सामाजिक न्याय की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता है। उनके अनुसार, विभिन्न जातियों की वास्तविक आबादी और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं होने पर शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और आरक्षण सहित सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

'ओपन-एंडेड' प्रश्न के तरीके पर सवाल उठाया

कांग्रेस नेताओं ने जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए अपनाए गए 'ओपन-एंडेड' प्रश्न के तरीके पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार, भारत में एक ही जाति अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों तथा भाषाओं के आधार पर पहचानी जाती है। पत्र में कहा गया है, ऐसे में यदि एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग-अलग नामों से दर्ज होंगे, तो एक जाति हजारों नामों में बंट जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे, और जाति जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही अनुपयोगी हो जाएगा। खरगे और राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि मौजूदा व्यवस्था से देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुल आबादी का सही आंकड़ा कैसे सामने आएगा?

प्रधानमंत्री पत्र पर संज्ञान लें

देश में करीब 4,200 जातियां हैं और प्रत्येक राज्य के पास जातियों की अपनी सूची है, जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार के पास भी अपनी सूची है। रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो उसे खरगे और राहुल द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र पर संज्ञान में लेना चाहिए। केंद्र ने बीते 14 अगस्त को जनसंख्या गणना के चरण के तहत उत्तरदाताओं से पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित किया। इनमें जाति और कोविड रोधी टीकाकरण की जगह से संबंधित सवाल भी शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों में जनगणना एक से 30 सितंबर तक होगी।

जयराम ने इसे बताया सिर्फ लीपापोती

उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह जनगणना कराई जा रही है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ लीपापोती है। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले कई वर्षों तक जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते थे, लेकिन इसकी घोषणा के बाद से लगातार यू-टर्न ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरगे और राहुल इस विषय पर प्रधानमंत्री को कई पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। रमेश ने 21 सितंबर, 2021 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कहा गया था कि जातिगत जनगणना कराने के लिए पहले से जातियों की सूची तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के दौरान 215 जातियों की सूची तैयार की गई थी और तेलंगाना में भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी।

पहले से तैयार 'ड्रॉप-डाउन' सूची का सुझाव दिया

कांग्रेस नेताओं ने जातियों की पहले से तैयार 'ड्रॉप-डाउन' सूची का सुझाव दिया है, जिसके तहत जनगणना के फॉर्म या डिजिटल ऐप में जातियों के आधिकारिक नाम पहले से उपलब्ध हों और गणनाकर्ता संबंधित व्यक्ति द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर सूची में से उपयुक्त जाति का चयन कर सके। पत्र में सुझाव दिया गया है कि ऐसी सूची मौजूदा सरकारी सूचियों, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित सूचियों तथा भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण जैसे आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार की जा सकती है। खरगे और राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार और तेलंगाना में किए गए जातिगत सर्वेक्षणों में भी सूची आधारित व्यवस्था अपनाई गई थी। उन्होंने दोनों राज्यों के सर्वेक्षणों में इस्तेमाल की गई जाति सूचियों को प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के साथ संलग्न किया है। खरगे और गांधी के पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को वर्तमान प्रश्नावली को रद्द कर सभी राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत के बाद पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी चाहिए।

बांके बिहारी के चढ़ावे में 'बंदरबांट'

सुप्रीम कोर्ट नाराज, मंदिर की तिजोरी में पहुंचे एक-एक पैसा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और धनराशि के गलत तरीके से निकाले जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया एक-एक पैसा या तो मंदिर की दानपेटियों में पहुंचे या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो। अदालत ने कहा कि चढ़ावे की राशि को किसी भी तरह से इधर-उधर किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दानपेटी के सामने पैसे इकट्ठा करने का वीडियो पेश

सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थिति रिपोर्ट रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में बेहद गंभीर स्थिति सामने आई है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अदालत के समक्ष तस्वीरें और एक वीडियो भी पेश किया।

2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक पर टिकीं निगाहें

राम मंदिर को मिलेंगे नए सीईओ और प्रवक्ता

रामजन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर दो सितंबर को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम है। बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीईओ और प्रवक्ता की नियुक्ति पर फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा लंबे समय से रिक्त चल रहे अन्य पदों को भरने पर भी मंथन होगा। यहां श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और लगातार विस्तार पा रही व्यवस्थाओं के बीच ट्रस्ट प्रशासनिक ढांचे को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 नामों का पैनल चयन समिति की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। इन नामों में सेवानिवृत्त आईपीएस राजेश पांडेय, सेवानिवृत्त आईएएस दिनेश चंद्र और योगेश्वर राम मिश्रा का नाम बताया जा रहा है।

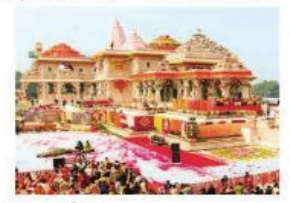

'सेवायतों' की किसी भी रुकावट को गंभीरता से लेंगे

पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर की कोषागार तक पहुंचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेवायतों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इसमें किसी भी तरह की बाधा पैदा की जाती है तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए गर्व की बात कही

यूपीआई के 10 साल बेमिसाल

पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल भुगतान में भारत ने बनाई दुनिया में नई पहचान

▶▶ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की एक दशक की सफलता को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में एक बड़ा बदलाव बताया है। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसने भारत में डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। सुरक्षित और अंतर-संचालनीय रियल टाइम भुगतान सुविधा देने वाला यूपीआई भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे सफल स्तंभों में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी व्यापक पहुंच और बड़े पैमाने पर सफलता प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई से जुड़े अपने अनुभव साझा करने का भी आह्वान किया।

लेन देन में 13 हजार गुना वृद्धि दर्ज हुई

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यूपीआई के जरिए होने वाले लेनदेन की संख्या में पिछले दस वर्षों के दौरान करीब 13 हजार गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के माध्यम से केवल 1.78 करोड़ लेनदेन हुए थे, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। इसी अवधि में लेनदेन का कुल मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीखने की अनिवार्यता पर राज्यभर में मचा बवाल

केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने लिखा सीएम फडणवीस को पत्र

मराठी नहीं आए तो रद्द न करें टैक्सी चालकों के लाइसेंस बल्कि प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दें

▶▶ नई दिल्ली

महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य करने के बीच केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया है कि मराठी नहीं जानने वाले गरीब टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के खिलाफ तत्काल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। उन्होंने चालकों को मराठी सीखने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय देने और इस अवधि में प्रशिक्षण व प्रोत्साहन के जरिए उन्हें भाषा सीखने का अवसर देने का सुझाव दिया है। मराठी सीखना जुड़ाव की दृष्टि से सराहनीय है, लेकिन नई भाषा को सीखने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए।

भाषा सीखने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दें

सिंह ने कहा कि हाल के मुंबई दौरे के दौरान उन्हें कई गैर-मराठी नागरिकों और ऑटो-रिक्शा चालकों से मिलने तथा उनकी चिंताओं को सीधे समझने का अवसर मिला। उन्होंने महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी सीखने की पहल को सामाजिक जुड़ाव मजबूत करने वाला कदम बताया, लेकिन पर्याप्त समय देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंह ने सुझाव दिया कि मराठी नहीं जानने वाले चालकों को कम से कम एक वर्ष का अवसर दिया जाए। यदि वे मराठी नहीं सीख पाते हैं तो भी उनके लाइसेंस तत्काल रद्द नहीं किए जाएं। जल्दबाजी में की गई दंडात्मक कार्रवाई से असंतोष पैदा हो सकता है और क्षेत्रीय एवं भाषायी विवाद बढ़ने की आशंका भी रहेगी। यह पत्र ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए मराठी के व्यावहारिक ज्ञान को अनिवार्य करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है।

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 3,000 मामले आने से हड़कंप, सरकार बोली

हालात नियंत्रण में, दवाओं की कोई कमी नहीं

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के मामलों में अचानक हुई वृद्धि ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। शहर में अब तक इस संक्रमण के लगभग 3,000 मामले सामने आ चुके हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्वास्थ्य व्यवस्था और रोकथाम के उपायों की समीक्षा के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई है।

■ स्वास्थ्य मंत्री पंकज ने कहा- लोग पैनिक न करें

कीमतें बढ़ने पर दिल्ली सरकार नेफेड से खरीदेगी चीनी और प्याज

सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में चीनी और प्याज की उपलब्धता की निगरानी करेगी और कीमतें बढ़ने की स्थिति में नेफेड से दोनों वस्तुएं खरीदेगी, ताकि लोगों को ये सस्ती दरों पर मिल सकें। गुप्ता ने एक समीक्षा बैठक में चीनी और प्याज की उपलब्धता का आकलन किया और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

सीएम रेखा ने की आपात बैठक

लोग बरतें सावधानियां चिकित्सकों से संपर्क करें

इस मामले पर दिल्ली सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अस्पतालों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं।

नोएडा में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा

एक दिन में 105 नए मामले, 8 गुना बढ़े

जिले में मंगलवार को स्वाइन फ्लू के मामलों में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में 105 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 120 पहुंच गई। सोमवार को जिले में स्वाइन फ्लू के केवल 15 मरीज दर्ज थे। 24 घंटे के भीतर मामलों में हुई इस तीव्र बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को सामने आए सभी 120 मामलों की जांच निजी अस्पतालों में कराई गई है।

7 ताकतें भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी

भाजपा पीएम मोदी के 'सप्तधारा' संदेश को जनता तक ले जाएगी

▶▶ नई दिल्ली

भाजपा 4-5 दिन में 'सप्तधारा' का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि वे इसके अलग-अलग पहलुओं को समझ सकें। भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'सप्तधारा' यानी विकास की 7 धाराओं वाले लक्ष्य की सराहना की है। पात्रा ने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ने एक लक्ष्य चाहिए। देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है, जब सही नेता सही समय पर सही लक्ष्य चुनता है। पात्रा ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश के सामने यह लक्ष्य रखा था। पात्रा ने प्रधानमंत्री के 'सप्तधारा' रोडमैप का जिक्र करते हुए बताया कि भारत के भविष्य की राह विनिर्माण, तकनीक, तेज संपर्क और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

मुलुंड पेट्रोल पंप विवाद में कांग्रेस कूदी, ऑर्किड स्कूल की दूरी को लेकर उठाए सवाल

संवाददाता

मुंबईः मुलुंड पूर्व में प्रस्तावित पेट्रोल पंप को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता एवं विधायक आदित्य ठाकरे के दौरे के बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है.इस मामले में कांग्रेस ने भी हस्तक्षेप करते हुए प्रस्तावित पेट्रोल पंप के लिए आरक्षित भूखंड का मौके पर निरीक्षण किया और जमीन से सटे ऑर्किड स्कूल की दूरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.कांग्रेस प्रवक्ता राकेश शंकर शेट्टी ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पंप स्थल का दौरा किया.शेट्टी के मुताबिक, मौके पर नाप लेने के दौरान पेट्रोल पंप के लिए प्रस्तावित जगह और ऑर्किड स्कूल के बीच की दूरी 5 मीटर से भी कम दिखाई दी उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल पंप के लिए स्कूल जैसी संवेदनशील जगह से निर्धारित सुरक्षा दूरी का पालन किया जाना आवश्यक है.

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र० /अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण अमित कुमार अग्रवाल आ० प्रेम चंद अग्रवाल, निवासी 303 डाइमंड ए०वी०आईपी एस्टेट, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर, अंशुल अग्रवाल आ० प्रेमचंद अग्रवाल, निवासी हाउस नं0 6 के, संजीवनी मेडिकल काम्पलेक्स, जेल रोड़, अमित मेडिकल एजेन्सी, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर -011 मोहल्ला लखनपुर रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 4531/12 रकबा 0.02 एकड़ भूमि को अनावेदक/केता नवीन कुमार अग्रवाल आ० मोहन लाल अग्रवाल, निवासी म०नं0-7, स्ट्रीट नंबर-1. अग्रसेन वार्ड, नगर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 02/09/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा, के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 17/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं अनुसुकला सिंह (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/

पत्नी देवबहादुर सिंह गाँव/शहर कछिया तहसील बिहारपुर

जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम अनुसुकला सिंह (पुराना नाम) से बदल कर अनशुक्ला (नया नाम) रख लिया है।

नाबालिग पुत्री/पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक/पालक द्वारा प्रमाणित)

मैं देवबहादुर सिंह (माता/ पिता/ पालक का नाम)

सुपुत्र/सुपुत्री प्रताप सिंह गाँव/शहर कछिया

तहसील बिहारपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम अनुसुकला सिंह (पुराना नाम) से बदल कर अनशुक्ला (नयाँ नाम) रख लिया है।

देवबहादुर सिंह

छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं थेओदीर टोप्पो पिता जुलयुस, निवासी ग्राम रूपसेरा, रूपसेरा, बगीचा, जिला-जशपुर, बगीचा, छत्तीसगढ़ 496224 ने अपने नाम थेओदीर टोप्पो (Theodir Toppo) से बदल कर थेओदोर टोप्पो (Theodor Toppo) रख लिया है।

थेओदीर

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं डमुघर सिदर (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र / सुपुत्री/पत्नी धोबसाय, शहर / गाँव-दीवानपुर सिदारपारा, तहसील-पत्थलगांव जिला जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम डमुघर सिदर (पुराना नाम) से बदल कर डमरूधर पोर्ते (नया नाम) रख लिया है।

डमुघर सिदर

छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं सुरजमनी सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी कामदेव राम निवासी मकान न-04, हरार्डीपा, गांव-हरार्डीपा, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ 496336 ने अपने नाम सुरजमनी(SURAJMANI) से बदल कर सुरजमुनी बाई (SURAJMUNI BAI) रख लिया है।

सुरजमनी

(नाबालिक के लिए) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं रेशमा टोप्पो पति मुक्ति प्रकाश टोप्पो निवासी गांव / शहर मकान न-79, वार्ड न 02, बोडापहरी तहसील-बगीचा जिला जशपुर छत्तीसगढ़ 496224 ने अपने नाबालिक पुत्री का नाम मयरा मर्सी टोप्पो (MYRA MERCY TOPPO) से बदल कर मायरा टोप्पो (MAYRA TOPPO) रख लिया है।

रेशमा टोप्पो

(नाबालिक के लिए) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं मनमोहनी बाई सुपुत्र/सुपुत्री / पत्नी मोहन राम गांव/ग्राम मकान नं. 39, वार्ड नं. 09 उपर गम्हरिया, गम्हरिया बगीचा, पोस्ट-बगीचा जिला-जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपने नाबालिक पुत्र/पुत्री का नाम रोनल प्रजापति (Ronal Prajapti) से बदल कर सोनल प्रजापति (Sonal Prajapati), रख लिया है।

मनमोहनी

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं पुजा देवी (Puja Devi) सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी प्रकाश राम गांव / शहर 71, पुरानी बस्ती, तारागढ़, पोस्ट भेडीमुड़ा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ ने अपने नाम पुजा देवी (Puja Devi) से बदल कर प्रिसीला खलखो (Prisila Xalxo), रख लिया है।

पुजा देवी

(नाबालिक के लिए) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं परमानन्द साय पैंकरा पिता उदय साय पैंकरा गांव / शहर 220, मैनी, मैनी, पोस्ट-दुगार्पारा तहसील-बगीचा जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ - 496224 राज्य ने अपने नाबालिक सुपुत्र का नाम अरब पैंकरा (Arab Painkra) से बदल कर आरव पैंकरा (Aarav Painkra), रख लिया है।

परमानन्द साय पैंकरा

(नाबालिक के लिए) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं निर्मला बाई सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी प्रवीण कुमार नाग गांव/ग्राम सरईपानी पोस्ट-सरईपानी तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपने नाबालिक पुत्र का नाम क्रिश नागवंशी (Krish Nagvanshi) से बदल कर कृष्णा नागवंशी (Krishna Nagwanshi), रख लिया है।

निर्मला बाई

(नाबालिक के लिए) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्ररूप-(एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं सरस्वती बाई पति अशोक कुमार निवासी गांव/शहर गैलुंगा, पोस्ट-बछ्राओं, जिला-जशपुर छत्तीसगढ़ 496224 ने अपने नाबालिक पुत्र का नाम अनुरंग कुमार (Anurang Kumar) से बदल कर अनुराग कुमार (Anurag Kumar), रख लिया है।

सरस्वती बाई

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं रीनसिंह सिदर (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी डमरूधर पोर्ते शहर /गाँव- दीवानपुर सिदारपारा, तहसील-पत्थलगांव जिला जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम-रीनसिंह सिदर (पुराना नाम) से बदल कर रीना पोर्ते. (नया नाम) रख लिया है।

रीनसिंह सिदर

मुख्यमंत्री ने बाबा कर्मेश्वर का किया रुद्राभिषेक, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड राजपुर अंतर्गत ग्राम कर्रा में आयोजित श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने प्राचीन बाबा कर्मेश्वर धाम में भगवान शिव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर ग्राम कर्रा में मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबा कर्मेश्वर की कृपा से यह क्षेत्र निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक विकास कार्यों

को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम कर्रा की पावन भूमि पर श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा का आयोजन होना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कथावाचक आचार्य दिव्यानंद जी महाराज को नमन करते हुए आयोजन समिति और समस्त श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर बनी रहे और प्रत्येक परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो।

छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने का हो रहा कार्य

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म, संस्कृति और आस्था की समृद्ध परंपराओं की भूमि है। यह माता कौशल्या की जन्मभूमि और प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेश के गांव-गांव में प्राचीन शिवालयों, देवी मंदिरों और लोक आस्था के केंद्रों की गौरवशाली परंपरा रही है। राज्य सरकार इस समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भगवान श्रीराम से गहरा और आत्मीय संबंध है। राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन का अवसर मिल रहा है। अब तक लगभग 50 हजार श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था और तीर्थ दर्शन की अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए तीर्थ दर्शन योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत देशभर के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। अब तक लगभग 10 हजार श्रद्धालु इस योजना का लाभ लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कर चुके हैं।

शांति और विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा बस्तर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कर्मेश्वर के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दशकों तक हिंसा से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आज शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्रा सहित बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी विकास कार्यों को निरंतर गति दी जाएगी। क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए यहां आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ग्राम कर्रा स्थित बाबा कर्मेश्वर धाम क्षेत्र की लोक आस्था का प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां विराजमान शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। जनश्रुतियों के अनुसार लगभग नौवीं-दसवीं शताब्दी में साल के वृक्ष के खोल में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और तभी से यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में श्री कर्मेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। बाबा कर्मेश्वर से क्षेत्र की लोक मान्यताओं का भी गहरा संबंध है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार पुराने समय में जब क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी, तब ग्रामीण भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते थे। शिवलिंग पर गाय के गोबर का लेप लगाने की भी एक पारंपरिक मान्यता रही है।

विभागीय टेट पर बनी सहमति, शिक्षामंत्री से मिला शिक्षक संगठन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार को शिक्षक संगठनों और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच हुई बैठक में विभागीय टेट कराने पर सहमति बन गई। करीब आधे घंटे चली बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय टेट की प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। इस परीक्षा में केवल कार्यरत शिक्षक ही शामिल होंगे और यह सामान्य टेट से अलग शिक्षा विभाग के स्तर पर आयोजित की जाएगी।

शिक्षक संगठनों के मुताबिक, 25 अगस्त को प्रदेशभर में किए गए आंदोलन के बाद सरकार की ओर से उन्हें चर्चा के लिए बुलाया

गया था। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे शिक्षक नेताओं ने शिक्षामंत्री से मुलाकात की। बैठक में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक एवं संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन, शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

विभागीय टेट पर बनी सहमति

बैठक में शिक्षक संगठनों ने टेट को लेकर अपनी आपत्तियां और मांगें रखीं। इस दौरान शिक्षामंत्री ने विभागीय टेट आयोजित करने पर सहमति जताई और संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए।

पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग का आगाज, 6 टीमें दिखाएंगी दमखम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हॉकी को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाली यह देश की पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग होगी, जिसे हॉकी इंडिया लीग की तर्ज पर प्रोफेशनल स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। लीग के मुकाबले संभावित रूप से 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को नवीन विश्राम भवन में लीग के लोगो, टैगलाइन और शुभंकर का अनावरण किया।

छह टीमें मैदान में उतरेंगी

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। सभी टीमें लीग चरण में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले खेलेंगी। अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और इसके बाद फाइनल मुकाबले से चैंपियन का फैसला होगा। सभी मैचों में हॉकी इंडिया की ओर से नियुक्त अंपायर और तकनीकी अधिकारी मौजूद रहेंगे।

युवा खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हॉकी की समृद्ध परंपरा रही है और प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। लीग के जरिए स्थानीय खिलाड़ियों को देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुभव और प्रतिस्पर्धी माहौल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

चलव रे संगी, हॉकी खेलबो बनी टैगलाइन

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की टैगलाइन ह्यचलव रे संगी, हॉकी खेलबोह्न रखी गई है। छत्तीसगढ़ी बोली में यह टैगलाइन अपनत्व और आमंत्रण का संदेश देती है। लीग का लोगो छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर आधारित है। इसमें केसरिया और हरे रंग के साथ आगे बढ़ती नारंगी रेखा प्रदेश की प्रगति और आगे बढ़ने की भावना को दशार्ती है। लीग का आधिकारिक शुभंकर ह्यबघवाह्न नामक बाघ है। इसे छत्तीसगढ़ के जंगलों, वन्यजीव विरासत, साहस और शक्ति का प्रतीक बनाया गया है। शुभंकर खिलाड़ियों के जुझारूपन और मैदान पर दबदबा कायम करने की भावना को दशार्ता है।

मैचों के साथ मनोरंजन का भी तड़का

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रखा जाएगा।

सकारात्मक व निष्पक्ष लेखन से ही संभव है समाज परिवर्तन - कुलपति प्रो. दयाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (केटीयू), रायपुर में शासकीय महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, भानुप्रतापपुर के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान बस्तर अंचल से आए विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय की उन्नत प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया और कुलपति प्रो. मनोज दयाल से संवाद कर जनसंचार की बारीकियों को समझा।

पत्रकारिता एक सशक्त व नए समाज का निर्माण का माध्यम

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सकारात्मक और निष्पक्ष पत्रकारिता ही एक सशक्त व नए समाज का निर्माण कर सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे मीडिया क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता को निखारें और समाचार पत्र, टीवी, रेडियो तथा डिजिटल मीडिया का नियमित तुलनात्मक अध्ययन करें। भ्रमण में विद्यार्थियों ने केटीयू के टीवी स्टूडियो, कम्युनिटी रेडियो, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और निमार्णाधीन एआई व मीडिया रिसर्च लैब का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज के शिक्षक श्रीदाम ढ़ाली के मार्गदर्शन में आए छात्रों ने विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो ह्यसंवाद 98.2 एफएमह्न में अपने संदेश भी रिकॉर्ड किए। इस दौरान छात्रों ने जनसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन व जनसंपर्क विभाग के प्राध्यापकों और शोधार्थियों से मुलाकात कर विश्वविद्यालय के सृजनात्मक क्लबों व शोध पीठों की कार्यप्रणाली को समझा।

विद्यार्थियों ने कहा अत्यंत ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक अनुभव

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दयाल, कुलसचिव सुनील शर्मा और सहायक कुलसचिव देव सिंह पाटिल सहित विभिन्न विभागाध्यक्षों से मार्गदर्शन प्राप्त कर इसे एक अत्यंत ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक अनुभव बताया।

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने संवाद कर उनके जीवन में आ रहे बदलाव की सराहना की

राज्य के मुखिया से आत्मीय बातचीत कर अभिभूत हुई हितग्राही महिलाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बालोद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह के अवसर पर बालोद जिले के महतारी वंदन योजना से लाभान्वित 05 हितग्राहियों से बातचीत कर इस योजना के फलस्वरूप उन्हें मिल रहे लाभ के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह उन्हें मिलने वाली 01 हजार रुपए की राशि से उनके जीवन में आ रहे व्यापक बदलाव की भूरी-भूरी सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय से आत्मयी बातचीत कर बालोद जिले के सभी हितग्राही महिलाएं बहुत ही अभिभूत नजर आ रही थीं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय बहुत ही सहज एवं आत्मीय ढंग से जिले के 05 महिला हितग्राहियों से बातचीत कर इस योजना के माध्यम से जीवन में हो रहे बदलाव के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर नगर पंचायत डौण्डीलोहारा निवासी श्रीमती जुही सोनी ने बताया कि उन्होंने महतारी वंदन योजना के माध्यम से लोन लेकर ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई मशीन का कार्य प्रारंभ किया है। इस कार्य से में सुधार एवं बदलाव के लिए बहुत ही कारगर एवं उपयोगी साबित हुआ है। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कियाउन्हें प्रतिमाह से 06 से 07 हजार रुपए प्रतिमाह की आमदनी प्राप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए महतारी वंदन योजना उनके जीवन स्तर। इसी तरह ग्राम हरदी निवासी श्रीमती भूमिका साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से संवाद करते हुए बताया कि उन्होंने महतारी वंदन योजना की राशि से सीमेंट का गमला एवं तुलसी चैरा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। इस कार्य से उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग सोशल मीडिया के कार्य में भी लगा रही है। भूमिका साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार के महतारी वंदन योजना को अपने जैसे अनेक जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बताते हुए इस योजना की भूरी-भूरी सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना से मिल रहे लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम कोरगुड़ा निवासी श्रीमती सरोज देवांगन ने इस योजना की मुक्तकंठ से सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से मिलने वाली प्रतिमाह मिलने वाली राशि से आटा चक्की का कार्य प्रारंभ किया है। जिससे उन्हें प्रतिमाह 03 से 04 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। इसी तरह इस योजना की सराहना ग्राम तुड़मुड़ा निवासी श्रीमती बसंती बाई ने भी राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना को अपने जैसे अनेक जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस योजना से मिल रहे राशि के लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस योजना से मिल रहे राशि से छोटा व्यापार प्रारंभ किया है। वे आसपास के बाजार में जाकर चना, फल्ली आदि खाद्य सामग्रियों की बिक्री कार्य कर रही हैं। इससे उन्हें प्रतिमाह 05 से 06 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है। मुख्यमंत्री साय ने इस योजना से मिल रहे राशि के फलस्वरूप हितग्राहियों के जीवन में आ रहे व्यापक बदलाव को महतारी वंदन योजना की वास्तविक सार्थकता बताते हुए इसकी सराहना की है। श्री साय ने महतारी वंदन योजना के सभी हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस योजना से प्रतिमाह मिलने वाले राशि का सदुपयोग करने को कहा।

नवा रायपुर को देश की अग्रणी ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित करने पर जोर : ओपी चौधरी

मंत्री चौधरी ने नवा रायपुर में 119.89 करोड़ की आवासीय परियोजना का किया भूमिपूजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12 फेस-2 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का भूमिपूजन किया।मंत्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर को देश की अग्रणी ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत एचआईजी और एमआईजी श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण होगा। मांग को देखते हुए इसी सेक्टर में अगले चरण में 704 नए फ्लैट (128 एचआईजी, 320 एमआईजी और 256 एलआईजी) भी बनाए जाएंगे।

बिना मांग के नहीं बनेगी कॉलोनी

मंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को कर्जमुक्त करने के लिए 700 करोड़ का ऋण चुकाया गया है। अब नई नीति बनाई गई है कि बिना मांग के कोई आवासीय परियोजना शुरू नहीं होगी। 60% बुकिंग होने या पहले 3 महीने में 30% बुकिंग होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ताकि मकान खाली न रहें। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कहा कि एसओआर से बेहतर टाइल्स, फिटिंग्स और आधुनिक रंगों का उपयोग किया जाए, भले ही लागत 5 से 10 प्रतिशत बढ़ जाए।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव

ने मंडल की वर्तमान कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा मांग आधारित परियोजनाओं, बेहतर आवासीय सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में मंडल की गतिविधियों में तेजी आई है और नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया है। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि सेक्टर-12 फेस-2 में शेष 29.20 एकड़ भूमि पर एचआईजी एवं एमआईजी श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों का बेस विक्रय मूल्य 45.70 लाख रुपए से 85.17 रुपए लाख तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए सेक्टर-12 फेस-2 में ही आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। इनमें 128 एचआईजी, 320 एमआईजी एवं 256 एलआईजी श्रेणी के फ्लैट शामिल होंगे। इन आवासों का बेस विक्रय मूल्य 16.76 लाख रुपए से 40.47 लाख रुपए तक प्रस्तावित है।

अब तक का विस्तार

आयुक्त अवनीश शरण ने बताया कि मंडल ने 2007 से अब तक सेक्टर-27 में 2665, सेक्टर-29 में 3012 और सेक्टर-12 फेस-1 में 450 भवन पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर-16, 30 और 34 में 4544 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 1871 लोगों को सौंपे जा चुके हैं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि सेक्टर-12 फेस-2 के नए 348 भवनों का बेस मूल्य 45.70 लाख से 85.17 लाख तक होगा, जबकि आगामी 704 फ्लैट का मूल्य 16.76 लाख से 40.47 लाख तक प्रस्तावित है।

पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्यों की शिकायत पर 1 वर्ष बाद भी कार्रवाई नहीं

तमोर पिंगला का मामला, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। वन्यजीवों और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए संवेदनशील माने जाने वाले तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र में कथित अवैध वृक्ष कटाई और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं को लेकर की गई शिकायत पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने का मामला सामने आया है।शिकायत कर्ताओं के अनुसार 7 जनवरी 2025 को कलेक्टर के नाम स्मरण पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में की गई शिकायतों के आधार पर तत्काल जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन आज तक मामले में न तो कोई प्रभावी विभागीय कार्रवाई सामने आई और न ही शिकायतकर्ताओं को जांच के निष्कर्ष से अवगत कराया गया।

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभ्यारण्य क्षेत्र में वन संपदा से जुड़ी गतिविधियां सामान्य वन क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील मानी जाती हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब ऐसे क्षेत्रों में सूखी लकड़ी उठाने तक के लिए अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, तब निर्माण कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर हरे-भरे पेड़ों की कटाई के आरोपों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।शिकायतकर्ता के मुताबिक तमोर पिंगला अभ्यारण्य में वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य कराए गए। इन कार्यों के दौरान कई स्थानों पर हरे-भरे पेड़ों की कटाई, वन संरक्षण संबंधी नियमों की अनदेखी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

इस मामले को लेकर पहले भी संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासन को शिकायत दी गई थी। शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद 7

जनवरी 2025 को पुन: स्मरण पत्र देकर मामले की जांच कराने की मांग की गई।

लेकिन स्मरण पत्र दिए जाने के बाद लंबा समय गुजर गया। आरोप है कि आज दिनांक तक न तो कोई स्पष्ट विभागीय जांच सामने आई, न जिम्मेदारी तय हुई और न ही कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच का परिणाम सार्वजनिक किया गया। तमोर पिंगला क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे संवेदनशील इलाके में निर्माण कार्य के दौरान यदि वास्तव में हरे-भरे पेड़ों की कटाई हुई है तो यह केवल वन संपदा के नुकसान का मामला नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरणीय संतुलन और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास से जुड़ा गंभीर विषय है। शिकायतकर्ताओं ने गेम रेंज तमोर के ई. क्र.-3, कक्ष क्र.-814 सहित पिंगला एवं खोड़ गेम रेंज के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से संबंधित वृक्ष कटाई की जांच कराने की मांग की गई है। सवाल यह है कि कितने पेड़ और किसकी अनुमति से काटे गए? कटाई से पहले और बाद का रिकॉर्ड क्या है, काटे गए पेड़ों का हिसाब कहां है? और जिन निर्माण कार्यों के लिए पेड़ काटे गए, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? इन सवालों का जवाब जांच पश्चात ही सामने आ सकता है। स्मरण पत्र में केवल वृक्ष कटाई ही नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने कैम्पा मद सहित विभिन्न योजनाओं से कराए गए कार्यों की स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश, माप पुस्तिका, भुगतान अभिलेख और मौके पर हुए वास्तविक कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।

आरोप यह भी है कि कुछ मामलों में निर्माण कार्यों से जुड़े वाहनों और बिलों को लेकर अधिकारियों की भूमिका की जांच आवश्यक है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं तो यह सार्वजनिक धन के उपयोग और विभागीय पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करेगा। एक तरफ सरकार वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों के संरक्षण और कैंपा जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च कर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की दिशा में प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि अनियमितता या नियमों की अनदेखी होती है तो यह सरकारी प्रयासों पर पानी फेरने जैसा होगा।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि योजनाओं का उद्देश्य जंगल और वन्यजीवों का संरक्षण है, लेकिन यदि निर्माण कार्यों के नाम पर प्राकृतिक वन संपदा को नुकसान पहुंचता है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, तो योजनाओं के वास्तविक उद्देश्य पर ही सवाल उठने लगते हैं। यदि जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और यदि जांच नहीं हुई तो शिकायत को इतने लंबे समय तक लंबित रखने का कारण क्या है?

उच्चस्तरीय जांच की मांग

शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की जांच उसी विभाग के स्तर तक सीमित न रखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच समिति से कराई जाए। संबंधित अवधि में हुए सभी निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण, वृक्ष कटाई का भौतिक सत्यापन, कैम्पा एवं अन्य मदों के भुगतान का वित्तीय परीक्षण तथा संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आरोप गलत हैं तो प्रशासन जांच कर स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। तमोर पिंगला जैसे संवेदनशील वन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की शिकायत, उसके बाद स्मरण पत्र और फिर लंबे समय तक कार्रवाई का अभाव, यह पूरा घटनाक्रम अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

पेण्डारी स्वा. केंद्र की बदहाली दूर करने पांच पंचायतों ने उठाया बीड़ा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। लगातार बारिश के कारण जिले के पेण्डारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत से पानी टपकने और सीपेज की समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रतापपुर मुकेश तायल के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजीत दीवान के साथ निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और स्वास्थ्यकर्मियों की बैठक हुई।

इसमें पेण्डारी, नवाडीह, सोनपुर, पोड़ीपा एवं चंद्रेली पंचायत के सरपंचों ने आपसी सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र की छत की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। वहीं बिजली, पंखे और पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर की व्यवस्था जीवनदीप समिति के माध्यम से कराने, आयुष्मान सेवा जल्द शुरू करने तथा साफ-सफाई, दवा वितरण, आपातकालीन सेवा और मरीजों से बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस पहल को पांच पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुधारने की दिशा में सराहनीय और अनुकरणीय कदम माना जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान मंडल महामंत्री मोहन लाल भोय सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

मेडलीएपीआर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हुई स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। मेडिको-लीगल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मंगलवार को यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने की। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में ई-मेडलीएपीआर के क्रियान्वयन की स्थिति, प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों तथा उनके त्वरित निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने ई-मेडलीएपीआर से संबंधित समस्याओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी निराकरण तथा नियमित समन्वय बैठक आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित संस्थानों में ई-मेडलीएपीआर के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका को प्रभावी बनाने,

सीसीटीएनएस, ई-मेडलीएपीआर के माध्यम से प्राप्त एमएलसी एवं पीएम रिक्वेस्ट का समय पर निराकरण करने तथा चिकित्सकों द्वारा एमएलसी रिपोर्ट ऑनलाइन जनरेट किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। लंबित एमएलसी एवं पीएम रिपोर्ट के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ई-मेडलीएपीआर के माध्यम से एमएलसी एवं पीएम रिपोर्ट की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत ऑनलाइन एवं समयबद्ध बनाना स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आवश्यक चिकित्सकीय एवं कानूनी दस्तावेजों की उपलब्धता में पारदर्शिता, त्वरित संप्रेषण तथा प्रकरणों के समयबद्ध निष्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ई-मेडलीएपीआर के संचालन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई करेंगे। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में एसडीओपी अभिषेक पैंकरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सामु. व प्राथमिक स्वा. केन्द्र के अधिकारी कर्मचारियों, जिले के थाना-चौकी प्रभारी व सीसीटीएनएस कर्मचारियों की सहभागिता रही। अधिकारियों ने ई-मेडलीएपीआर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समन्वय, सतत निगरानी और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	197880 द्वितीय आमंत्रण 19.08.2026	जिला बलरामपुर रामानुजगंज के भगवानपुर के मेंढ़ारी मार्ग लंबाई 5.80 कि.मी. पुल– पुलिया सहित निर्माण कार्य।	864.35
2	197875 तृतीय आमंत्रण 19.08.2026	विचारपुर से धोबघट्टी तक पहुंच मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. एवं डी 1 नहर से धोबघट्टी होते हुए लालपुर कला तक मार्ग लंबाई 3.30 कि. मी. कुल लंबाई 5.30 कि.मी. का निर्माण कार्य।	713.08
3	197876 द्वितीय आमंत्रण 19.08.2026	जिला बालोद के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन में 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन का वाटर सप्लाई,सेनेटरी फिटिंग,बाऊण्ड्रीवाल, 'एफ' टाईप क्वार्टर, गार्ड रूम, पहुंच मार्ग एवं विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।	251.81
4	197887 द्वितीय आमंत्रण 19.08.2026	कोनी (नगर निगम के बाजू) फारेस्ट रेस्ट हाऊस होते हुए पत्रकार कॉलोनी आशोक नगर आंशाबंद लिंक मार्ग लंबाई 3.70 कि.मी. का निर्माण कार्य।	821.95
5	197890 तृतीय आमंत्रण 19.08.2026	पुसौर में बहुउद्देशी स्पोर्ट्स स्टेडियम भवन का निर्माण कार्य, वा.स.से. फि. विद्युतीकरण एवं पहुंच मार्ग का कार्य।	459.39
6	197914 पंचम आमंत्रण 19.08.2026	जिला खैरागढ़– छुईखदान–गण्डई के राजनांदगांव कवर्धा मार्ग के कि. मी. 51/10 (राज्य मार्ग 05) पर कदम नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	327.89
7	197918 चतुर्थ आमंत्रण 19.08.2026	जिला बीजापुर के बीजापुर –आवापल्ली– चितलनार –इंजारम मार्ग के कि.मी. 5/6 मरीवागू नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	416.03
8	197975 द्वितीय आमंत्रण 20.08.2026	मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर के मनेन्द्रगढ में कॉलेज छात्राओं हेतु हॉस्टल निर्माण कार्य, जमा मद।	257.99
9	197976 द्वितीय आमंत्रण 20.08.2026	एन.एच. 130 ए से नेहरू चौक उस्लापुर पुल तक मार्ग लंबाई 3.20 कि. मी. एवं टेलीफोन एक्सजेंस पहुंच मार्ग लंबाई 3.29 कि.मी. कुल लंबाई 6.49 कि.मी. का निर्माण कार्य।	926.49
10	197977 द्वितीय आमंत्रण 20.08.2026	जिला रायपुर के धमनी गनौद (लिंक मार्ग) लंबाई 1.45 कि.मी. का निर्माण कार्य, पुल पुलिया सहित।	227.57
11	198034 प्रथम आमंत्रण 20.08.2026	जिला दुर्ग के स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय नेवई भिलाई में कुलपति निवास ('बी'टाईप 1 नग) कुलसचिव, कुलाधिसचिव , प्राध्यापक, सह– प्राध्यापक निवास ('डी 'टाईप 13 नग) 250 सीटर बालक छात्रावास, सहायक प्राध्यापक निवास ('ई' टाईप 10 नग आवास) एवं वर्कशॉप भवन का वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग, सेप्टिंक टैंक, सम्प वैल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग , बोरवैल, बाऊण्ड्रीवाल का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (जमा मद अंतर्गत)।	2653.23
12	198046 द्वितीय आमंत्रण 20.08.2026	जिला रायपुर के आरंग नगर स्थित शासकीय बद्रीप्रसाद लोधी महाविद्यालय में 300 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य, वॉटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतीकरण कार्य सहित।	671.25
13	198059 द्वितीय आमंत्रण 20.08.2026	जिला जांजगीर चांपा के पुराना एन.एच. पर हसदेव नदी में जर्जर गेमन में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1301.72

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क्र. 02, सं.क्र. 05 से सं.क्र. 07 दिनांक 31.08.2026 सं.क्र. 11 दिनांक 10.09.2026 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदओं के लिए दिनांक 07.09.2026 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते हैं।

मुख्य अभियन्ता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जी-262702950/2

करसी-मकनपुर के वीडियो ने खोली पोषण व्यवस्था की पोल, पूरे ब्लॉक में जांच की मांग, प्रतापपुर में रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता पर सवाल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण पूरक पोषण आहार योजना के तहत गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाले रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता को लेकर प्रतापपुर क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करसी मकनपुर क्षेत्र से सामने आए वीडियो के बाद ग्रामीणों ने कथित रूप से घटिया और मिलावटी रेडी-टू-ईट सामग्री वितरित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रतापपुर क्षेत्र में इसके जांच की मांग की है। मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस पूरक पोषण आहार का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर कुपोषण से बचाना है, उसकी गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों के अनुसार करसी-मकनपुर में सामने आई सामग्री की स्थिति ऐसी बताई जा रही है, जिसे देखकर उसके सेवन को लेकर आशंका पैदा होती है। उनका आरोप है कि यदि यही सामग्री गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों तक पहुंच रही है तो यह सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ा आक्रोश

करसी-मकनपुर से सामने आए वीडियो में ग्रामीणों ने रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राजकुमार पैकरा, कुश पैकरा, राजधानी पैकरा, अमरनाथ पैकरा, बृजमोहन पैकरा, सुधन घसिया, शामवती रजक, गंगोत्री सारथी, मनियारो सारथी, विफन रजक सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों और माताओं को दिया जाने वाला पोषण आहार स्वयं ही गुणवत्ता के सवालों से घिरा हुआ है। यदि सामग्री वास्तव में खराब या मिलावटी पाई जाती है तो इसके सेवन से लाभ के बजाय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ग्रामीण पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल चाहते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि मामला केवल करसी-मकनपुर तक सीमित मानकर जांच की गई तो वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आएगी। उनकी मांग है कि प्रतापपुर विकासखंड के सभी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित रेडी-टू-ईट के नमूने लिए जाएं और अधिकृत प्रयोगशाला से उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। इसके साथ ही उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण से जुड़े दस्तावेजों का भी मिलान करने की मांग की गई है। कितना उत्पादन हुआ, किस समूह या संस्था ने तैयार किया, कहां पैकिंग हुई, कितनी मात्रा में सामग्री केंद्रों तक पहुंची और

लाभार्थियों को वास्तव में कितना वितरण किया गया इन सभी बिंदुओं की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बाहर से तैयार रेडीमेड सामग्री लाकर पैकिंग और वितरण किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। कुछ समूहों के पास आवश्यक मशीनरी और उत्पादन व्यवस्था उपलब्ध होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोषण आहार कहां और किस व्यवस्था के तहत तैयार किया जा रहा है। वहीं यदि समूहों के पास आवश्यक संसाधन मौजूद हैं तो उनकी भौतिक जांच भी कराई जानी चाहिए। इससे उत्पादन व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकता है।ग्रामीणों ने रेडी-टू-ईट योजना में कथित अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग की जांच की मांग भी की है।

उनका का कहना है कि यदि व्यवस्था पूरी तरह निर्धारित मानकों के अनुसार चल रही है तो निष्पक्ष जांच के बाद स्थिति स्वत: स्पष्ट हो जाएगी। वहीं किसी स्तर पर गड़बड़ी प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं-शुभम

मामले की शिकायत पर जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में रेडी-टू-ईट गुणवत्ता विहीन पाया गया तो संबंधित सप्लायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल करसी-मकनपुर के वीडियो ने प्रतापपुर की पोषण व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या रेडी-टू-ईट वास्तव में मानकों पर खरा उतर रहा है, या फिर कहीं व्यवस्था में बड़ी चूक हो रही है? इसका जवाब अब जांच टीम की रिपोर्ट से ही सामने आएगा। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि बच्चों और माताओं के पोषण से जुड़े मामले में जांच कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे प्रतापपुर विकासखंड की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए।

सरपंच के निरीक्षण में छतरंग बालक आश्रम अधीक्षक मिले गायब, नाले के गंदे पानी में नहाते पाए गए बच्चे

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के दूरस्थ अंचल ओड़गी क्षेत्र के ग्राम छतरंग स्थित शासकीय बालक आश्रम इन दिनों अपनी अव्यवस्था के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। आश्रम की दम तोड़ती व्यवस्था से चिंतित गांव के सरपंच सुभाष सिंह मरकाम के द्वारा कलेक्टर को शिकायत पत्र सौपकर आश्रम की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है जो काफी गम्भीर है। अपने शिकायत पत्र में सरपंच ने बताया है कि उन्होंने 23 अगस्त को आश्रम का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया गया है कि आश्रम अधीक्षक चंद्रमणी खरे अधिकांश समय गायब रहते हैं। वे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन आते हैं और वापस चले जाते हैं। जून 2026 में प्रभार ग्रहण करने के बाद से वे आज दिनांक तक एक भी दिन आश्रम में रात नहीं रुके हैं। निरीक्षण के दौरान आश्रम में दर्ज 48 बच्चों में से मात्र 16 बच्चे ही उपस्थित मिले। आश्रम और बालक छात्रावास में बच्चों की मूलभूत सुविधाओं का

पूरी तरह से अभाव है। यहाँ बच्चों को मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे सभी बच्चे बिना मच्छरदानी के सोने को मजबूर हैं और उनमें मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही, छात्रावासों में सोने के लिए पर्याप्त बेड और गद्दों की भी भारी कमी है। आश्रम में पानी की गंभीर समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। छोटे-छोटे बच्चों को हॉस्टल से 500 मीटर दूर जंगल के किनारे, नदी और तालाब के गंदे पानी तथा खेतों से बहते पानी में नहाना पड़ रहा है। इस स्थिति के चलते बच्चे कभी भी गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, वहीं बरसात के दिनों में गहरे तालाब के पास किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

कार्रवाई की मांग

सरपंच श्री मरकाम ने कलेक्टर से तत्काल इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, लंबे समय से गायब चल रहे लापरवाह अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा छात्रावास में पानी की तत्काल उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ताकि आश्रम में रह रहे बच्चो को उनका बुनियादी हक व सुविधा मुहैय्या हो सके।

'जो देश का नहीं वह नबी साहब का नहीं हो सकता'

जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर एक मंच से सर्वधर्म गुरुओं ने दिया अमन और भाईचारे का पैगाम

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मुस्लिम समाज के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को शहर में जश्ने ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पूरी शिद्दत, श्रद्धा, शालीनता व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मोहल्लों से जुलूस निकलकर मुख्य मार्ग से होते हुए कला केंद्र मैदान पहुंचा। सीरतुन्नबी कमेटी अंबिकापुर द्वारा कला केंद्र मैदान में भव्य, शानदार और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सभी धर्म, संप्रदाय, वर्ग के प्रबुद्धजन, धार्मिक गुरुओं सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं तथा वक्ताओं ने संबोधित किया। ईसाई समाज के प्रमुख धर्मगुरु बिशप स्वामी डॉक्टर एंथोनी बड़ा, सिख समाज के वक्ता हरदीप सिंह जिंदल, हिंदू धर्म के वक्ता अंजनी कुमार पांडे तथा मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलाना सगीर मिस्बाही और मौलाना हमीद रजा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर प्रकाश डाला। धर्मगुरूओं ने कहा कि जब दुनिया में बुराई का अंधेरा छाया था, ऐसे प्रतिकूल माहौल में पैगंबर साहब का जन्म हुआ। उन्होंने मानवता, अहिंसा, महिला अधिकार, लोकतंत्र, समाजवाद और न्याय के साथ खड़े होने का और इंसाफ का संदेश दिया। उन्होंने दूसरे धर्म का सम्मान करने, अनुशासन, सौम्यता, उदार और ईमानदार होने की सीख दी। वक्ताओं ने कहा महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों ने भी स्वीकार किया कि, वे मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलकर आगे बढ़े। वक्ताओं ने देश प्रेम पर जोर देते हुए कहा देश प्रेम आधा ईमान है, जो देश का नहीं वह नबी साहब का नहीं हो सकता। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के हाजी रहमत खान,यासीन अंसारी,पार्षद हसन खान, अख्तर सिद्दीकी, बाबर इदरीशी , शादाब आलम रिज़वी, हाजी अख्तर, मो.जाकिर, सादिक खान, कमाल खान, गुलशेर खान, साबिर मुन्ना, अशफाक कमर, सलमान इंजीनियर, हाजी रिजवान, मो.वसीम का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस अवसर पर शफी अहमद, मोहम्मद इस्लाम, इरफ़ान सिद्दीकी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, अशफाक अली, रशीद अंसारी, दानिश रफीक, नगर पालिक निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, विद्यानंद मिश्रा, संजय अंबष्ट, द्वितेंद्र मिश्रा, आलोक दुबे, संजय मितल, प्रकाश, रियाजुल, जिलानी खान, इसरार अहमद, सादिक हुसैन, तनवीर, सनउवर हुसैन, तनवीर, सिकंदर, इरफान, हनीफ, मुजीबुल रहमान, सद्दाम खान, जमाल खान, आरजू, नसीम, खान, कलाम, अविनाश, दुर्गेश गुप्ता सहित काफी संख्या में सर्वधर्म के लोगों की उपस्थिति रही।

सांप्रदायिक सद्भावना की अनोखी मिसाल

सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सरगुजा के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने कहा कि सीरतुन्नबी कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष सांप्रदायिक सद्भावना की जो मिसाल पेश की जाती है, वह अनोखी है। सभी वर्गों को शामिल कर शहर के आपसी भाईचारा और समरसता को मजबूती देना सराहनीय है। स्वागत भाषण कमेटी के अध्यक्ष मेराज गुड्डू, संचालन फैजान अहमद और आभार प्रदर्शन कार्यकारी अध्यक्ष नियाजउद्दीन खान निक्की द्वारा किया गया।

प्रतिभाओं का किया गया सम्मान

इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, शूटिंग, कुश्ती तथा कैरम में जिला और राज्य में अंबिकापुर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, यूपीएससी और सीजीपीएससी में सफलता हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। समाज सेवा में सराहनीय कार्य के लिए रजा यूनिटी फाउंडेशन, गौ सेवा मंडल तथा मुस्लिम युवा मंच सहित शहर के सभी मदरसों के होनहार छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले दो सदस्य मसूद आलम तथा फैजान अहमद और विभिन्न मोहल्लों की सजावट में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाली कमेटियों को भी सम्मानित किया गया।

बटवाही में निकला जुलूसे मोहम्मदी, अंजुमन गोसिया कमेटी के नेतृत्व में गूंजे नारे

लुण्ड्रा। पैगम्बर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर सरगुजा जिले के लुण्ड्रा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवाही में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। अंजुमन गोसिया कमेटी के तत्वावधान में भव्य जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अहले सुन्नत के लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

जुलूस की शुरुआत बटवाही स्थित मस्जिद से हुई। जुलूस मिशन चौक होते हुए बस स्टैंड रघुनाथपुर, पुलिस चौकी और सुमेरपुर तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन, उनके आदर्शों और शिक्षाओं को याद किया। कार्यक्रम के दौरान मिलाद महफिल और सीरत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पैगंबर की शिक्षाओं और मानवता, भाईचारे एवं सद्भाव का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में इमाम उमर नूरानी, सदर मो. ताहिर हुसैन, हाफिज सफीक कादरी, मो. इसराइल अंसारी, मो. हैदर अली, मो. असलम खान, मो. मुजफ्फर चिश्ती, मो. मजीबुल्लाह अंसारी, मो. मुस्ताक अंसारी, मो. इसराफिल अंसारी, सहबूब अंसारी, मौलवी युसूफ, मो. अख्तर, इकरामुल, मो. फिरोज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

पुलिस की रही कड़ी सुरक्षा-जुलूस को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी आर.एन. पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

युवक के पास मिला गौ मांस, पुलिस ने किया गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना पुलिस ने मायापुर के चांदनी चौक में छापा मारकर एक व्यक्ति के पास से गौ-मांस बरामद किया है। मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित दास पिता स्व. मिश्री लाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त की सुबह चांदनी चौक में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में गाय का मांस होने की सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी, इसके बाद कोतवाली पुलिस टीम चांदनी चौक पहुंची। मौके पर झारखंड निवासी इरफान अंसारी अपने किराये के मकान में गाय के ताजा मांस को प्लास्टिक की पन्नी में रखे हुए मिला। सभी ने इसकी पहचान गाय के मांस के रूप में की। बजरंग दल ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

वंदना मेहता की सड़क हादसे में मौत, भाई ने सवाल उठाया-अवकाश के दिन क्यों बुलाया कार्यालय

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के रामानुजगंज नाका चौक पर बीते शनिवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत वंदना मेहता को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद विभाग में शोक है, वहीं स्वजन में अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। मृतका केदारपुर निवासी स्वर्ण मेहता और मनीष मेहता की बहन थीं। शनिवार को शासकीय अवकाश था। विभागीय अधिकारियों के बुलावा पर वंदना कार्यालय आई थीं, इसके बाद घर नहीं लौटीं। मृतका के भाई स्वर्ण मेहता का आरोप है कि, दिनभर काम कराने के बाद शाम को अंधेरा

होने के बाद उन्हें छोड़ा गया। ने सीधे तौर पर अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि, रामानुजगंज नाका चौक शहर का व्यस्ततम और खतरनाक चौक बन चुका है। शाम ढलते ही यहां अंधेरा पसर जाता है, स्ट्रीट लाइटें या तो बंद रहती हैं या रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर भारी वाहन तेज गति से गुजरते हैं। शनिवार शाम को वंदना कार्यालय से निकलकर ऑटो पकड़ने के लिए चौक पर खड़ी थीं, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक ब्रेक तक नहीं लगा सका।

विभागीय अफसरों की संवेदनहीनता के कारण हुई घटना

मृतका के भाई स्वर्ण मेहता ने आरोप लगाया कि यह घटना विभागीय अफसरों की संवेदनहीनता के कारण हुई है। एक तरफ शासन महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते नहीं थकती है, दूसरी तरफ महिला कर्मचारियों को अवकाश के दिन भी अंधेरे तक कार्यालय में रोक कर रखा जाता है। न तो उनके आने-जाने की कोई व्यवस्था की जाती है और न ही सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। जब शनिवार को अवकाश था, तो किस कार्य की इतनी अनिवार्यता थी कि एक महिला कर्मचारी को शाम तक रोकना पड़ा? स्वजन ने मामले की जांच की मांग की है

समाजसेवियों का होटल मानस पैलेस में सम्मान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नगर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं कवि आचार्य दिग्विजय सिंह द्वारा शहर के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। होटल मानस पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में समाजहित में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर राजेन्द्र बहादुर सिंह, सुरेश राम बुनकर, अंकुर सिन्हा, संजय ठाकुर, सत्यम शिवम, मनीष टोप्पो, अनीता साहनी, सुल्ताना सिद्दीकी,

अनीस साहनी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक सेवा मुस्लिम महिला समिति को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समिति की ओर से नाजिया खातून, शहनाज खान, निशा खातून सहित अन्य पदाधिकारियों ने सम्मान प्राप्त किया। वक्ताओं ने समिति द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की।

बच्चों ने बड्स, बिंदी, टॉफी और शादी के कार्ड से बनाई कलात्मक राखियां

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के त्रिकोण चौक स्थित सरगुजा शिल्प में कलात्मक राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ संरक्षिका डॉक्टर पुष्पा सोनी ने किया।

प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली। यहां विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर, डे बोर्डिंग स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई लगभग 200 राखियां प्रदर्शित की गई हैं। बच्चों ने बड्स, बिंदी, मोती, टॉफी, शादी के कार्ड और भगवान के चित्रों का उपयोग कर कलात्मक राखियां बनाई हैं। इसके साथ ही शहर की हस्तशिल्प में निपुण नेहा वर्मा और रेखा भार्गव ने भी अपनी कलात्मक राखियों की प्रदर्शनी लगाई है। इस अवसर पर संयोजिका वंदना दत्ता, वहीदा अहमद, वंदना सिंह, स्मिता तिवारी, नेहा वर्मा, जयंती सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। यह प्रदर्शनी प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।

सैनिक स्कूल का 18वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल होंगे मुख्य अतिथि

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के गौरव सैनिक स्कूल अंबिकापुर अपना 18वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहा है। इसको लेकर विद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विद्यालय के प्राचार्य कर्नल राजेश बेंडा ने बताया कि, समारोह आगामी 1 सितंबर, मंगलवार को सुबह 11 बजे से सैनिक स्कूल परिसर, अंबिकापुर में आयोजित होगा।

समारोह के मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल, मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे मुख्य अतिथि के आगमन और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ होगी। वृक्षारोपण, सेरेमोनियल लैंप का प्रज्वलन, केक सेरेमनी रिचुअल, स्वागत भाषण, कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेजेंटेशन सेरेमनी सहित अन्य आयोजन होंगे।

18 साल का गौरवशाली सफर

सैनिक स्कूल अंबिकापुर की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। महज 18 साल के सफर में ही इस स्कूल ने अनुशासन, शिक्षा और खेल तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां से पढ़े कई कैडेट्स एनडीए के माध्यम से भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनकर देश सेवा कर रहे हैं। स्कूल परिसर में स्थापित युद्धक टैंक टी-55 इसकी सैन्य विरासत का प्रतीक है। फाउंडर्स डे के दौरान कैडेट्स द्वारा मार्च पास्ट, हॉर्स राइडिंग, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का कुशलक्षेम जाना विधायकों ने

छ.ग.फ्रंटलाइन सीतापुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से भाजपा के सरगुजा जिला अध्यक्ष सहित विधायकों ने बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात करके उनका कुशलक्षेम जाना। गौरतलब है कि, विगत दिनों मध्य प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद से वे अस्वस्थ चल रहे हैं और वर्तमान में नई दिल्ली में उनका उपचार जारी है। मुलाकात के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, विधायक लुण्ड्रा प्रबोध मिंज और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर शीघ्र स्वस्थ

होने की कामना की। इन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पुनः उसी ऊर्जा, उत्साह और समर्पण के साथ संगठन और जनसेवा के कार्यों में जुटें, ऐसी कामना है।

ट्रेक्टर से गिरकर घायल हुए दिव्यांग की इलाज के दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ट्रेक्टर से गिरने सहित चार अलग-अलग मामलों में घायल दो महिला और दो पुरूष की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया है। शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिला के पस्ता थाना अंतर्गत ग्राम उलिया निवासी उषा तिर्की पिता स्व. रोदन राम 46 वर्ष, बाएं पैर से दिव्यांग था। बीते 19 अगस्त को वह अपने भतीजा के साथ ट्रेक्टर लेकर ग्राम पस्ता में खेत की जोताई करने गया था। वापस आते समय रास्ते में मादरसरई के पास अनियंत्रित होकर ट्रेक्टर से नीचे गिर गया। स्वजन उसे राजपुर स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे, यहां से रेफर करने पर 20 अगस्त को मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराए थे, यहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई।

स्कूटी में बैठते समय गिरी महिला, मौत-अन्य घटनाओं में स्कूटी में बैठ रही ब्रम्ह रोड अंबिकापुर निवासी सुशीला देवी पति स्व. कृष्णा प्रसाद गुप्ता 67 वर्ष की मौत हो गई। मृतिका मंगलवार को अपरान्ह करीब 3 बजे केवाईसी कराने के लिए आयुष केशरी के साथ जाने निकल रही थी। स्कूटी में बैठते समय वह अचानक सिर के बल गिरी। स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान शाम 5.15 बजे उसकी मौत हो गई।

कीटनाशक सेवन किए वृद्ध की मौत-सूरजपुर जिला के प्रतापपुर थाना अंतर्गत ग्राम करसी निवासी रामचरण पिता स्व. रूमघुट कोड़ाकू 67 वर्ष की कीटनाशक के सेवन से मौत हो गई। मृतक 23 अगस्त को पैदल बाजार की ओर गया था, इसी दौरान अज्ञात कारणों से कीटनाशक का सेवन कर लिया। स्वजन उसे प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र से रिफर करने पर मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पैदल आ रही महिला गिरी, हो गई मौत-मायके से पैदल घर लौट रही बसंती यादव पति राजनाथ 60 वर्ष, रास्ते में गिर गई, अस्पताल लाते तक उसकी मौत हो गई। मृतिका कोतवाली थाना अंबिकापुर के कांतिप्रकाशपुर की रहने वाली थी। 24 अगस्त को वह अपने भतीजा चंद्रबलि के साथ सूरजपुर जिला के भटगांव थाना अंतर्गत जरही गई थी, और अपने मायका ग्राम बोझा में ही रूक गई थी। 25 अगस्त को दोनों वापस आने के लिए ग्राम बोझा से खड़गवां जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वह अचानक गिर गई। स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एनएच पर बेकाबू ट्रक स्ट्रीट लाइट के खंभे तोड़ते डिवाइडर पर चढ़ा

बलेनो कार को ठोकर मारने के बाद चालक हो गया फरार

छ.ग.फ्रंटलाइन लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-130 पर मंगलवार को शाम करीब 8.30 बजे एक बेकाबू ट्रक के चालक ने जमकर तांडव मचाया और स्ट्रीट लाइट, कार को चपेट में लेते डिवाइडर पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक लखनपुर के केवरा चौक के पास अनियंत्रित हो गई। ट्रक हाईवे के किनारे लगे कई स्ट्रीट लाइट के खंभों को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद भी ट्रक नहीं रुका और आगे खड़ी एक बलेनो कार को पीछे से जोरदार ठोकर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी

के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही लखनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर अग्रिम पड़ताल कर रही है।

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर मोबाइल लेकर भागा

छ.ग.फ्रंटलाइन लुण्ड्रा। थाना क्षेत्र की एक महिला ने गांव के ही युवक पर देर रात घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसके पति 21 अगस्त को रायगढ़ काम करने गए हैं। 23 अगस्त को रात करीब 10 बजे खाना खाकर वह अपने दोनों बच्चों के साथ सोई थी। रात 11 बजे संतोष गोड़ दरवाजा खटखटाया, पूछने पर अपना नाम संतोष बताया और भैया से काम है कहते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहा। महिला ने बताया कि उसके पति नहीं हैं, और वह दरवाजा खोलने से मना कर दी। इसके बाद देर रात करीब 3 बजे संतोष बिना अनुमति के घर के अंदर घुस गया और उसके बिस्तर के पास आकर गलत नियत से हाथ-बांह पकड़ने लगा। नींद खुलने पर महिला ने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो संतोष गोंड़ था। युवक को सामने देखकर महिला हड़बड़ाकर उठने का कोशिश की, इस बीच उसका मोबाइल फोन गिर गया। आरोपी मोबाइल लेकर भागने लगा। महिला उसे पकड़ने कोशिश की तो उसका कंबल और लुंगी हाथ में आ गया। घटना की जानकारी वह संबंधियों को दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर